खबर पेज 7 पर

गंभीर समाचार

समय–समाज–संस्कृति

खबर पेज 8 पर

वर्ष -12 | अंक–24 | पाक्षिक समाचार पत्रिका | कोलकाता, रविवार 1 – 15 मार्च 2026 | मूल्यः 5 रुपये | RNI No.WBHIN/2014/59321, ISSN No. 2456/3005 Kolkata | कुल पृष्ठ – 8

सुविचार

- ज़िंदगी को ठंड और घमंड से बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि दोनों ही परिस्थितियों में इंसान अकड़ जाता है।
- आदमी हमेशा संकट में ही कुछ सीखता है..! ख़ुशी में तो वो पिछले सबक भी भूल जाता है..!!

शेरो-शायरी

- उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए।
- किस किस को बताएँगे जुदाई का सबब हम, तू मुझ से ख़फ़ा है तो ज़माने के लिए आ।

पीएम मोदी ने ब्रिगेड से भरी हुंकार

♦ बंगाल से 'महाजंगलराज' का होगा खात्मा

♦ दीवारों पर लिखी जा चुकी है बदलाव की इबारत

निज संवाददाता : प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कोलकाता की धरती से पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत के विकास का नया अध्याय लिखा जा रहा है। सड़क, रेलवे और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी 18 हजार करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इस दौरान पीएम मोदी ने टीएमसी सरकार पर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि बंगाल में बदलाव अब दीवारों पर भी लिखा जा चुका है और लोगों के दिलों में भी छप चुका है। अब बंगाल से निर्मम सरकार का अंत होकर रहेगा। अब बंगाल से महाजंगलराज का खात्मा होगा। पीएम ने कहा, ये प्रोजेक्ट पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत को नई रफ्तार देंगे, इनसे व्यापार और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, लाखों लोगों का जीवन आसान होगा, उन्हें नए अवसर मिलेंगे। आज देश में रेलवे को आधुनिक बनाने का तेज अभियान चल रहा है। हमारा ये संकल्प है कि पश्चिम बंगाल इस अभियान में पीछे न रहे। इसीलिए केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का भी तेजी से विस्तार कर रही है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने अपने संबोधन में ममता सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा

कि बंगाल में महाजंगलराज खत्म होगा, बदलाव अब दीवारों पर लिख चुका है। उन्होंने कहा कि निर्मन सरकार कुर्सी जाते देख बोखला गई है। उन्होंने कहा कि टीएमसी सरकार परिवर्तन को रोक नहीं पाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि एक बार फिर से बंगाल में कानून का राज होगा। उन्होंने कहा कि टीएमसी के किसी भी अत्याचारी को छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि निर्मम सरकार का काउंटडाउन शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि बंगाल से जंगलराज खत्म होकर ही रहेगा। उन्होंने कहा कि नए बंगाल की क्रांति का बिगुल बज चुका है। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल के विकास में बीजेपी दिन रात लगी है। उन्होंने कहा की निर्मम सरकार रैली में जनसैलाब को रोक नहीं पाई। मोदी ने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब बंगाल में कानून का राज लौटेगा। उन्होंने कहा कि कानून तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, और टीएमसी के अत्याचारों को भी नहीं बख्शा जाएगा। उन्होंने कहा कि यह निर्दयी सरकार चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, बदलाव की इस आंधी को रोक नहीं पाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि आज भी इस सभा को रोकने के लिए निर्मम सरकार ने सारे हथियार निकाल लिए। आप लोगों को आने से रोकने के लिए ब्रिज बंद करवा दिए, गाड़ियां रुकवा दी, ट्रैफिक जाम करवाया, भाजपा के झंडे उखड़वा दिए, पोस्टर फड़वा दिए। लेकिन निर्मम सरकार साफ-साफ देख लो, आज के जनसैलाब को रोक नहीं पाई हो। पीएम ने कहा किकिल टीएमसी ने इस रैली में आने वाले आप सभी लोगों को चोर कहकर गाली दी है। असली चोर कौन है, ये बंगाल की प्रबुद्ध जनता जानती है उन्होंने कहा कि अपनी कुर्सी जाते हुए देखकर यहां की निर्मम सरकार बौखला गई है।

इच्छामृत्यु पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने छेड़ दी जीवन गरिमा और कानून के बीच गहरी बहस

♦ लंबे और पीड़ादायक संघर्ष की कहानी है हरीश राणा का मामला

इच्छामृत्यु पर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला केवल एक कानूनी आदेश नहीं है। यह उस कठिन संतुलन की तलाश है जिसमें मानव गरिमा, परिवार की पीड़ा और कानून की मर्यादा तीनों को साथ-साथ समझा जा सके। आने वाले समय में यह बहस और गहरी हो सकती है और संभव है कि भारत को इस विषय पर एक स्पष्ट और व्यापक कानून बनाने की दिशा में भी कदम उठाना पड़े।

निज संवाददाता : भारत में जीवन के अधिकार को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार माना जाता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह बहस भी तेज हुई है कि क्या किसी व्यक्ति को गरिमा के साथ मरने का अधिकार भी होना चाहिए। गाजियाबाद के 31 वर्षीय हरीश राणा को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पैसिव इच्छामृत्यु की अनुमति दिए जाने के बाद यह सवाल एक बार फिर राष्ट्रीय बहस के केंद्र में आ गया है। यह फैसला केवल एक व्यक्ति के जीवन का निर्णय नहीं है, बल्कि यह उस जटिल स्थिति को भी सामने लाता है जिसमें आधुनिक चिकित्सा, कानून और मानवीय संवेदनाएं आपस में टकराती दिखाई देती हैं। हरीश राणा का मामला एक लंबे और पीड़ादायक संघर्ष की कहानी है। वर्ष 2013 में वह चंडीगढ़ में पढ़ाई कर रहे थे। उसी दौरान हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिरने के कारण उनके सिर में गंभीर चोट लगी। इस दुर्घटना के बाद उनका मस्तिष्क बुरी तरह प्रभावित हो गया और वह स्थायी रूप से कोमा जैसी अवस्था में चले गए। डॉक्टरों के अनुसार उनका ब्रेन डैमेज इतना गंभीर था कि उनके होश में आने की संभावना बेहद कम थी। पिछले लगभग 13 वर्षों से वह अचेत अवस्था में बिस्तर पर पड़े थे और उनका जीवन केवल कृत्रिम पोषण, दवाओं और जीवन रक्षक चिकित्सा प्रणाली पर निर्भर था। लंबे समय तक बिस्तर पर पड़े रहने के कारण उनके शरीर में कई तरह की जटिलताएं पैदा हो गई थीं। चिकित्सा रिपोर्ट के अनुसार लगातार लेटे रहने से उनके शरीर में बेड सोर यानी गंभीर घाव हो गए थे। डॉक्टरों की राय थी कि उनकी चेतना लौटने की संभावना लगभग समाप्त हो चुकी है। इस स्थिति में उनके माता-पिता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अपने बेटे के लिए इच्छामृत्यु की अनुमति मांगी।

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने एम्स की मेडिकल रिपोर्ट, विशेषज्ञों की राय और कानूनी प्रावधानों पर विचार करने के बाद पैसिव इच्छामृत्यु की अनुमति दे दी। अदालत ने माना कि जब कोई व्यक्ति वर्षों तक ऐसी स्थिति में रहता है जहां उसके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं होती और जीवन केवल मशीनों या कृत्रिम साधनों पर निर्भर होता है, तब गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार भी एक मानवीय प्रश्न बन जाता है। दरअसल इच्छामृत्यु का विषय चिकित्सा नैतिकता और कानून के सबसे जटिल मुद्दों में से एक है। इच्छा मृत्यु का अर्थ है किसी ऐसे व्यक्ति को मृत्यु की अनुमति देना जो असाध्य बीमारी, असहनीय दर्द या स्थायी अचेत अवस्था में हो और जिसके ठीक होने की संभावना न हो। आम तौर पर इच्छामृत्यु दो प्रकार की मानी जाती है एक्टिव इच्छामृत्यु और पैसिव इच्छामृत्यु। एक्टिव इच्छामृत्यु में डॉक्टर मरीज को ऐसी दवा या इंजेक्शन देते हैं जिससे उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। भारत सहित दुनिया के अधिकांश देशों में इसे अवैध माना जाता है क्योंकि इसे सीधे तौर पर किसी व्यक्ति की हत्या के समान माना जाता है। भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार जानबूझकर किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनना एक गंभीर अपराध है। दूसरी ओर पैसिव इच्छामृत्यु में डॉक्टर सीधे मृत्यु का कारण नहीं बनते, बल्कि जीवन रक्षक उपचार को हटा दिया जाता है। इसमें वेंटिलेटर हटाना, कृत्रिम भोजन बंद करना या इलाज रोक देना शामिल होता है। इसके बाद मरीज की मृत्यु स्वाभाविक रूप से होती है। भारत में सीमित परिस्थितियों में इसी प्रकार की इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता दी गई है। भारत में इच्छामृत्यु की कानूनी बहस का इतिहास लगभग पांच दशकों पुराना है, लेकिन इसे स्पष्ट रूप से समझने की शुरुआत 2011 के अरुणा शॉनबाग मामले से हुई। अरुणा शॉनबाग मुंबई के केईएम अस्पताल में नर्स थीं। 27 नवंबर 1973 की रात एक वार्ड बॉय ने उन पर हमला किया। हमले के दौरान उनके गले को लोहे की चेन से कस दिया गया, जिससे उनके मस्तिष्क तक ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक गई और उनका दिमाग गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। इस घटना के बाद अरुणा शॉनबाग स्थायी वेजिटेटिव स्टेट में चली गईं। वह लगभग 42 वर्षों तक अस्पताल के बिस्तर पर रहीं। चिकित्सा विज्ञान में इसे परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट कहा जाता है, जिसमें शरीर जीवित रहता है लेकिन चेतना लगभग समाप्त हो जाती है। 2009 में पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता पिंकी विरानी ने सुप्रीम कोर्ट में अरुणा के लिए इच्छामृत्यु की याचिका दायर की। उनका तर्क था कि अरुणा दशकों से ऐसी स्थिति में जीवन जी रही हैं जो मानवीय गरिमा के खिलाफ है। हालांकि केईएम अस्पताल की नर्सों ने इसका विरोध किया और कहा कि वे अरुणा की देखभाल कर रही हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने 7 मार्च 2011 को इस याचिका को खारिज कर दिया, लेकिन अपने फैसले में पहली बार पैसिव इच्छा मृत्यु को कुछ शर्तों के साथ अनुमति देने का रास्ता खोल दिया। यही फैसला आगे चलकर भारत में इच्छामृत्यु के कानून की आधारशिला बना। इसके बाद 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ''कॉमन कॉज़ बनाम यूनियन ऑफ इंडिया'' मामले में एक और ऐतिहासिक फैसला सुनाया। संविधान पीठ ने कहा कि गरिमा के साथ मरने का अधिकार भी संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा है। अदालत ने ''लिविंग विल'' को भी कानूनी मान्यता दी। इसका अर्थ यह है कि कोई व्यक्ति पहले से लिखित रूप में यह तय कर सकता है कि गंभीर बीमारी की स्थिति में उसे किस प्रकार का इलाज दिया जाए या नहीं दिया जाए। बेल्जियम ने भी 2002 में इसे वैध किया और 2014 में नाबालिग मरीजों के लिए भी सीमित परिस्थितियों में इसकी अनुमति दे दी। कनाडा ने वर्ष 2016 में मेडिकल असिस्टेंट डाइंग कानून लागू किया।

भारत में हालांकि स्थिति अलग है। यहां एक्टिव इच्छामृत्यु पूरी तरह अवैध है और केवल पैसिव इच्छामृत्यु को सीमित परिस्थितियों में अनुमति दी गई है। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अपने दिशा-निर्देशों में संशोधन किया। नए नियमों के अनुसार इच्छा मृत्यु से जुड़े मामलों में अस्पताल को दो मेडिकल बोर्ड बनाने होते हैं। दोनों बोर्ड मरीज की स्थिति का मूल्यांकन करते हैं और 48 घंटे के भीतर अपनी राय देते हैं।

मोदी की सभा से पहले गिरीश पार्क बना जंग का मैदान

♦ मंत्री शशि पांजा के घर पर फेंकी गईं ईंटें

♦ तृणमूल–बीजेपी की झड़प में ओसी हुए लहूलुहान

निज संवाददाता : शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिगेड रैली के दिन उत्तर कोलकाता का गिरीश पार्क इलाका जंग के मैदान में बदल गया। कहा जा रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राज्य मंत्री और तृणमूल कांग्रेस की नेता डॉ. शशि पांजा के घर पर ईंटें फेंकी। मंत्री ने आरोप लगाया कि उन पर भी हमला हुआ। जवाब में, बीजेपी ने दावा किया कि तृणमूल कार्यकर्ताओं ने पहले उनके जुलूस पर हमला किया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। दोनों पक्षों के बीच झड़प को रोकने की कोशिश करते समय ईंटों की बौछार में बाऊबाजार थाने के ओसी बप्पादित्य नस्कर समेत कई लोग घायल हो गए। एक घायल बीजेपी कार्यकर्ता को अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार दोपहर ब्रिगेड में एक मीटिंग करने आए थे। गिरीश पार्क में तृणमूल कार्यकर्ताओं के एक ग्रुप ने कहा कि उत्तर कोलकाता के अलग-अलग इलाकों से बीजेपी कार्यकर्ता शनिवार सुबह ब्रिगेड की ओर मार्च कर रहे थे। जब जुलूस गिरीश पार्क में मंत्री के घर के सामने से गुजरा तो तनाव शुरू हो गया। तृणमूल ने आरोप लगाया कि बीजेपी समर्थित बदमाशों ने ब्रिगेड जाने के नाम पर जानबूझकर शशि पांजा के घर को निशाना बनाया। तृणमूल कांग्रेस ने दावा किया कि ईंटों से हमले की वजह से घर की खिड़की के शीशे और मेन दरवाज़ा टूट गया। बीजेपी ने जवाबी आरोप लगाया कि तृणमूल के कार्यकर्ता शांतिपूर्ण जुलूस में रुकावट डालने के लिए पहले से ही मंत्री के घर के सामने जमा हो गए थे। उन्होंने दावा किया कि पुलिस चुपचाप खड़ी रही और रूलिंग पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही सबसे पहले जुलूस पर पत्थर फेंके। जिससे बीजेपी के उत्तर कोलकाता प्रेसिडेंट तमोघन घोष घायल हो गए।

पश्चिम एशिया युद्ध के बीच भारत की रसोई गैस सुरक्षा पर बड़ा संकट

निज संवाददाता : पश्चिम एशिया में भड़का युद्ध अब केवल भू-राजनीति का सवाल नहीं रह गया है, बल्कि यह सीधे भारत की रसोई और अर्थव्यवस्था तक पहुंच चुका है। अमेरिका-ईरान संघर्ष और उसके बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में पैदा हुई अस्थिरता ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा की कमजोरियों को उजागर कर दिया है। इसी खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने रसोई गैस यानी एलपीजी की आपूर्ति बनाए रखने के लिए असाधारण कदम उठाए हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने तेल रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं और अतिरिक्त उत्पादन को घरेलू खपत के लिए आरक्षित करने का फैसला किया है। यह कदम बताता है कि संकट की स्थिति में सरकार की पहली प्राथमिकता आम नागरिकों की रसोई को सुरक्षित रखना है। भारत की ऊर्जा संरचना का एक बड़ा सच यह है कि देश अपनी जरूरतों के मुकाबले एलपीजी का पर्याप्त उत्पादन नहीं करता। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2024-25 में भारत में कुल 31.3 मिलियन टन एलपीजी की खपत हुई, जबकि घरेलू उत्पादन केवल 12.8 मिलियन टन रहा। यानी देश की कुल जरूरत का लगभग 60 प्रतिशत से अधिक हिस्सा आयात के सहारे पूरा होता है। यही वजह है कि जब भी खाड़ी क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ती है तो उसका असर सीधे भारत की ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ता है। भारत के लिए यह निर्भरता इसलिए भी जोखिमपूर्ण है क्योंकि एलपीजी का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है। अनुमान है कि भारत के एलपीजी आयात का लगभग 85-90 प्रतिशत हिस्सा सऊदी अरब, कतर, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों से आता है। इन सभी देशों से आने वाली ऊर्जा आपूर्ति का मुख्य मार्ग स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है, जो विश्व ऊर्जा व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री गलियों में से एक है। जब यह मार्ग युद्ध या तनाव के कारण बाधित होता है तो पूरी वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हो जाती है। मौजूदा संघर्ष में भी यही स्थिति पैदा हुई है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के कारण इस समुद्री मार्ग में जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई है। इससे वैश्विक तेल और गैस बाजार में अनिश्चितता बढ़ी है और कई देशों ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर आपात योजनाएं बनानी शुरू कर दी हैं। भारत ने भी इसी पृष्ठभूमि में एलपीजी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आपातकालीन प्रावधानों का सहारा लिया है।

सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए गैस की आपूर्ति को प्राथमिकता के आधार पर नियंत्रित करने का फैसला किया है। इसके तहत घरेलू रसोई गैस की सप्लाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई

सरकार ने क्या बड़े फैसले लिए?

- रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का आदेश।
- घरेलू उपभोक्ताओं को गैस आपूर्ति में प्राथमिकता।

है। साथ ही पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी और वाहनों के लिए सीएनजी की आपूर्ति को भी 100 प्रतिशत सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा उर्वरक संयंत्रों को लगभग 70 प्रतिशत और उद्योगों को लगभग 80 प्रतिशत गैस उपलब्ध कराने की व्यवस्था तय की गई है। इन कदमों का उद्देश्य स्पष्ट है अगर ऊर्जा संकट गहराता है तो सबसे पहले घरों और परिवहन क्षेत्र को गैस मिलेगी, उसके बाद उद्योगों और अन्य क्षेत्रों को। सरकार ने एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए 25 दिन का इंटर-बुकिंग नियम भी लागू किया है, ताकि कोई भी उपभोक्ता तय समय से पहले सिलेंडर बुक न कर सके। लेकिन इस नीति का असर व्यावसायिक क्षेत्रों पर दिखने लगा है। देश के कई शहरों में कमर्शियल गैस सिलेंडरों की आपूर्ति घटने लगी है। होटल और रेस्टोरेंट उद्योग से जुड़े संगठनों का कहना है कि कई स्थानों पर कमर्शियल गैस की सप्लाई 10 से 20 प्रतिशत तक कम हो गई है। इससे खासतौर पर छोटे और मध्यम आकार के होटल-रेस्टोरेंट पर बड़ा दबाव पड़ा है, जो रोज मिलने वाली गैस सप्लाई पर ही निर्भर रहते हैं। कुछ शहरों में स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि होटल संगठनों ने कारोबार बंद होने की चेतावनी तक दे दी है। उनका कहना है कि अगर कमर्शियल गैस सिलेंडरों की नियमित आपूर्ति नहीं होती तो कई रेस्टोरेंट अगले कुछ दिनों में बंद होने की स्थिति में पहुंच सकते हैं। इसका असर केवल कारोबारियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उन लाखों कर्मचारियों और ग्राहकों पर भी पड़ेगा जो रोजमर्रा के भोजन के लिए इन प्रतिष्ठानों पर निर्भर हैं। सरकार ने इस समस्या को देखते हुए तेल विपणन कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति भी बनाई है। यह समिति होटल, रेस्टोरेंट और अन्य उद्योगों की गैस जरूरतों की समीक्षा करेगी और तय करेगी कि सीमित संसाधनों के बीच इन क्षेत्रों को कितनी आपूर्ति दी जा सकती है।

दरअसल यह संकट केवल तत्कालीन आपूर्ति का नहीं, बल्कि भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा रणनीति का भी सवाल है। पिछले एक दशक में देश में एलपीजी की खपत तेजी से बढ़ी है। उज्ज्वला योजना और शहरीकरण के कारण करोड़ों नए परिवार गैस पर निर्भर हो गए हैं। यही वजह है कि एलपीजी की मांग लगातार बढ़ रही है और आयात पर निर्भरता भी बढ़ती जा रही है। ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को भविष्य में ऐसे संकटों से बचने के लिए कई स्तरों पर तैयारी करनी होगी। सबसे पहला कदम घरेलू उत्पादन बढ़ाने का है। इसके लिए नई रिफाइनरियों, गैस प्रोसेसिंग संयंत्रों और पेट्रोकेमिकल ढांचे में निवेश बढ़ाना होगा। दूसरा महत्वपूर्ण कदम ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाना है, ताकि खाड़ी क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता कम हो सके। इसके अलावा एलपीजी के रणनीतिक भंडार तैयार करने की जरूरत भी लंबे समय से महसूस की जा रही है। जिस तरह भारत ने कच्चे तेल के लिए रणनीतिक भंडारण बनाए हैं, उसी तरह एलपीजी के लिए भी बड़े भंडार तैयार किए जाएं तो संकट की स्थिति में कुछ महीनों तक घरेलू जरूरतों को आसानी से पूरा किया जा सकता है।

पश्चिम एशिया का मौजूदा युद्ध शायद कुछ समय बाद खत्म हो जाए, लेकिन इसने भारत को एक अहम सबक जरूर दिया है। ऊर्जा सुरक्षा केवल आर्थिक नीति का विषय नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता से भी जुड़ा सवाल है। जब वैश्विक भू-राजनीतिक संकट पैदा होता है तो उसका असर सबसे पहले आम नागरिक की रसोई पर पड़ता है। भारत के सामने चुनौती यही है कि वह इस संकट को चेतावनी के रूप में ले और अपनी ऊर्जा नीति को अधिक मजबूत और आत्मनिर्भर बनाए। क्योंकि जब तक देश अपनी बढ़ती ऊर्जा जरूरतों के लिए बाहरी स्रोतों पर निर्भर रहेगा, तब तक दुनिया के किसी भी कोने में भड़की आग उसकी रसोई तक पहुंचती रहेगी।

1500 किमी दूर बैठकर डॉक्टर ने की सर्जरी!

कोलकाता के एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने कायम की मिसाल

हॉस्पिटल का दावा है कि रोबोट-असिस्टेड टेलीसर्जरी के ज़रिए इस तरीके से तीन मुश्किल यूरोलॉजिकल ऑपरेशन सफलतापूर्वक किए गए हैं। इस नई सर्जरी के दिन मरीज़ और डॉक्टर एक ही शहर में नहीं थे।

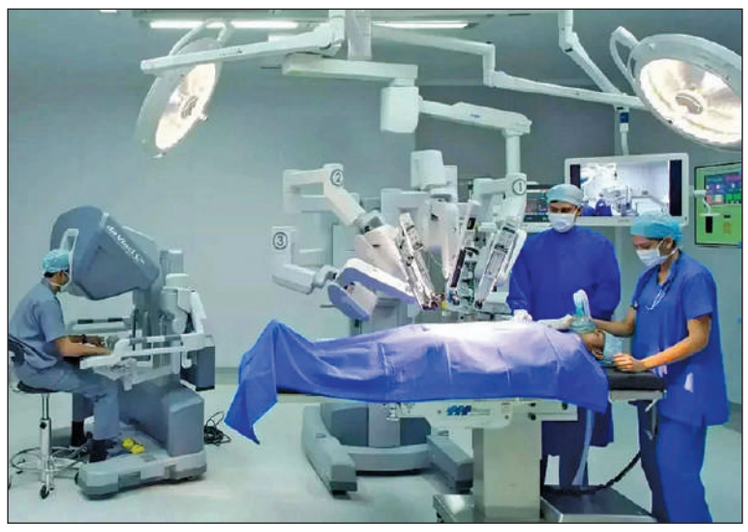

निज संवाददाता : एक डॉक्टर ने 1500 किमी दूर बैठकर सर्जरी की। यह कोई कहानी नहीं, सच है। महानगर कोलकाता में ऐसी ही एक अजीब घटना देखने को मिली। इस शहर ने देश में दूसरी और पूर्वी भारत में पहली ऐसी मिसाल कायम की है। गरियाहाट के पास ट्रायंगुलर पार्क में फोर्टिस हॉस्पिटल और किडनी इंस्टीट्यूट ने रोबोट की मदद से रिमोट सर्जरी का यह कारनामा किया है। अस्पताल का दावा है कि रोबोट-असिस्टेड टेली-सर्जरी के ज़रिए इस तरीके से तीन मुश्किल यूरोलॉजिकल ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरे किए गए हैं।

इस नई सर्जरी के दिन, मरीज़ और डॉक्टर एक ही शहर में नहीं थे। पहले दो मामलों में, मरीज़ कोलकाता के फोर्टिस हॉस्पिटल में थे, लेकिन ऑपरेशन 1500 किमी दूर नई दिल्ली में बैठे सर्जनों ने किए। रोबोटिक आर्म मरीज़ के पास था। रोबोट का कंसोल दिल्ली में था, जिसे वहीं बैठे सर्जन कंट्रोल कर रहे थे। डॉक्टर ने हाई-स्पीड डेडिकेटेड 5जी इंटरनेट कनेक्शन पर रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम को कंट्रोल करके लगभग 1,500 किमी की दूरी से सर्जरी की। तीसरे मामले में, स्थिति उलटी थी। मरीज़ फरीदाबाद में था। यहां के डॉक्टरों ने कोलकाता में बैठकर सर्जरी की। नतीजतन, यह टेली-रोबोटिक सर्जरी तीन शहरों - कोलकाता, दिल्ली और फरीदाबाद में की गई।

अब प्राइवेट अस्पतालों में भी फ्री में मिलेगी सरकारी वैक्सीन

बच्चों को टीबी, डिप्थीरिया, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, रूबेला, मीज़ल्स का मिलेगा टीका

निज संवाददाता : अब प्राइवेट अस्पतालों से भी फ्री सरकारी वैक्सीन मिलेंगी। ध्यान दें कि यूआईपी या इंडियन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन (भारतीय सार्वभौमिक टीकाकरण) प्रोग्राम के तहत बच्चों को टीबी, डिप्थीरिया, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, रूबेला, मीज़ल्स वगैरह 12 बीमारियों का टीका फ्री में लगाया जाता है। ये वैक्सीन बच्चे के जन्म के बाद सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से फ्री में मिलती हैं। अब से यह वैक्सीन प्राइवेट अस्पतालों में भी फ्री में लगाई जाएगी। राज्य सवास्थ्य विभाग के मुताबिक संबंधित जिले के प्राइवेट अस्पताल को जिले के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी को एक लिखित एप्लीकेशन (आवेदन) देनी होगी। स्वास्थ्य विभाग आवेदन की जांच करके उसे अनुमोदन करेगा। जन स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अनिर्वाण दोलुई ने कहा कि बड़े प्राइवेट अस्पतालों के अलावा कई दूसरे छोटे अस्पतालों में भी सरकारी वैक्सीनेशन प्रोग्राम (टीकाकरण कार्यक्रम) चलाया जा सकता है। इस नए अनुदेश से गलतियों से बचने में मदद मिलेगी। नए अनुदेश में बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। डॉ.अनिर्वाण दोलुई ने कहा कि अब से वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट से निपटने के इंतज़ाम और मज़बूत किए जाएंगे। प्राइवेट अस्पतालों को वैक्सीनेशन के लिए कौन से नियम मानने होंगे? स्वास्थ्य विभाग ने एक खास एसओपी जारी किया है और कहा है कि हर प्राइवेट अस्पताल को वैक्सीनेशन के लिए वेटिंग एरिया और वैक्सीनेशन सेंटर बनाने को कहा गया है। वैक्सीनेशन के बाद, पोस्ट-वैक्सीनेशन ऑब्ज़र्वेशन सेंटर (टीकाकरण के बाद अवलोकन केंद्र) भी बनाया जाए। वैक्सीनेशन सेंटर के बगल में ब्रेस्टफीडिंग (स्तनपान) के लिए एक अलग जगह बनाई जाए। ताकि नवजात के साथ मां को कोई दिक्कत न हो। कोई भी प्राइवेट अस्पताल हफ़्ते में ज़्यादा से ज़्यादा दो दिन वैक्सीनेशन सेशन (टीकाकरण सत्र) कर सकता है। संबंधित ज़िले के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी संभावित वैक्सीन पाने वालों की संख्या को देखते हुए दिन तय करेंगे।

आरवीएनएल को मैदान के चहारदीवारी में हरियाली ठीक करने का निर्देश

♦ माउंटेड पुलिस यूनिट के घोड़ों के हित में उठाया कदम

निज संवाददाता : पुलिस ने जोका-एस्प्लेनेड मेट्रो प्रोजेक्ट को लागू करने वाली एजेंसी रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) को मनोहर दास तारांग के पास पुराने मैदान के चहारदीवारी में हरियाली को ठीक करने का निर्देश दिया है, ताकि कोलकाता माउंटेड पुलिस के घोड़े अपनी नियमित अभ्यास के दौरान चर सकें। देश की सबसे पुरानी माउंटेड पुलिस यूनिट के घोड़े, अभी शहीद मीनार के पास एक अस्थायी चहारदीवारी में ट्रेनिंग ले रहे हैं, जहां घास नहीं है। अधिकारियों ने कहा कि घोड़ों के लिए चरना ज़रूरी है क्योंकि इससे उनकी गर्दन, कंधे और पीठ और जोड़ों की मसल्स को ठीक से स्ट्रेच करने में मदद मिलती है। कोलकाता पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा-हमने रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) से पुराने चहारदीवारी के उस हिस्से को ठीक करने के लिए कहा है जहां घास है। जहां अभी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हो रहा है। माउंटेड पुलिस, जिसमें 61 घोड़े हैं, 1840 में बनी थी। यूनिट ने पहले अपने कुछ घोड़ों को रॉयल कलकत्ता टर्फ क्लब में ट्रेनिंग दी थी, जिसके बाद 2006 में मैदान पर एक खास चहारदीवारी में शिफ्ट कर दिया गया। लगभग दो साल पहले, मेट्रो रेलवे ने शहीद मीनार के दक्षिण में एक प्लॉट पर अस्थायी चहारदीवारी बनाई थी क्योंकि मनोहर दास तरंग के पास मौजूदा चहारदीवारी को जोका-एस्प्लेनेड पर्पल लाइन कॉरिडोर पर एस्प्लेनेड मेट्रो स्टेशन बनाने के लिए लेना पड़ा था। पुलिस अधिकारी ने कहा-मेट्रो प्रोजेक्ट के तहत नए मैदान मार्केट को बनाने के लिए पुराने चहारदीवारी का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा ढक दिया गया है। चहारदीवारी के बाकी हिस्से में लोहे की रॉड, कंक्रीट के बचे हुए टुकड़े और दूसरा सामान बिखरा हुआ है। उन्होंने कहा-अगर ये सामान हटा दिए जाएं और उस हिस्से से झाड़ियां साफ कर दी जाएं, तो हमारे घोड़े वहां चरना शुरू कर सकते हैं। आरवीएनएल के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नए मार्केट को बनाने का काम पूरा होने के तुरंत बाद पुराने चहारदीवारी के एक हिस्से को ठीक कर दिया जाएगा। आरवीएनएल के एक सीनियर अधिकारी ने कहा-कंस्ट्रक्शन लगभग पूरा हो गया है, और हरियाली के बाकी हिस्से को ठीक करने से पहले निर्माण सामग्री और दूसरी चीज़ें जल्द ही हटा दी जाएंगी।

सुरबहार की महान गायिका अन्नपूर्णा देवी को उनके जन्म शताब्दी वर्ष पर डाक विभाग ने दी श्रद्धांजलि

निज संवाददाता : मैहर घराने की मशहूर सुरबहार वादक अन्नपूर्णा देवी के जन्म शताब्दी वर्ष की शुरुआत में, इंडिया पोस्ट ने अन्नपूर्णा देवी फाउंडेशन के साथ मिलकर उनके सम्मान में एक स्पेशल कवर और कैंसलेशन निकाला। जनरल पोस्ट ऑफिस (जीपीओ) में हुए इस लॉन्च में उनके दो शिष्य, नित्यानंद हल्दीपुर और बसंत काबरा शामिल हुए, जो फाउंडेशन का प्रतिनिधित्व करने के लिए मुंबई और जोधपुर से आए थे। हल्दीपुर ने हल्के-फुल्के अंदाज में अपनी और काबरा की ओर इशारा करते हुए कहा-वह एक लेडी द्रोणाचार्य थीं। उन्होंने पांडवों और कौरवों दोनों को सिखाया था। बांसुरी वादक ने अपने एकांतप्रिय गुरु के बारे में कहा, जिनकी 2018 में मौत हो गई थी-बदकिस्मती से, वह लाइमलाइट से दूर हो गईं। अगर वह पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बजाती रहतीं, तो आज उन्हें सबसे टॉप आर्टिस्ट माना जाता।बाद में उनके छात्रों ने उन्हें अपना मन बदलने के लिए मनाने की कोशिश की। उन्होंने बताया-लेकिन उनके लिए, (पब्लिक परफॉर्मेंस बंद करने का) प्रतिबद्धता पक्की थी।सरोद वादक बसंत काबरा ने बताया कि 1956 में अली अकबर कॉलेज ऑफ़ म्यूज़िक के उद्घाटन पर कोलकाता ने उनकी एक अनोखी एकल प्रदर्शन देखी थी। उन्होंने आगे कहा-बाबा (उस्ताद अलाउद्दीन खान, उनके और उस्ताद अली अकबर खान के पिता और गुरु और मैहर घराने के सबसे बड़े गुरु) ने उन्हें बजाने का हुक्म दिया, इसलिए वह मना नहीं कर सकीं। वरना, उनकी आठ-नौ दूसरी परफ़ॉर्मेंस में से ज़्यादातर पंडितजी (रवि शंकर, उनके पहले पति) के साथ हैं।कोलकाता रीजन की पोस्टल सर्विसेज़ की डायरेक्टर सुकृति गुप्ता ने कहा कि यह स्पेशल कवर एक म्यूज़िशियन और हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक की जानी-मानी टीचर के तौर पर उनके योगदान को श्रद्धांजलि है।

विधानसभा चुनाव के कारण बदली गई वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस परीक्षा की तिथि

24 मई को होगा एग्जाम

निज संवाददाता : जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन (जेईई) बोर्ड पूरे राज्य में बीटेक, फार्मेसी और आर्किटेक्चर प्रोग्राम में एडमिशन के लिए 24 मई को एंट्रेंस टेस्ट कराएगा। बोर्ड, जो आमतौर पर अप्रैल में एंट्रेंस टेस्ट कराता है, ने हाल ही में हुई मीटिंग में तारीखों पर फैसला किया। जेईई बोर्ड के रजिस्ट्रार दिब्येंदु कर द्वारा हस्ताक्षर की गई एक रिलीज़ में कहा गया- डब्ल्यूबीजेईईबी, पश्चिम बंगाल की अलग-अलग यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के इंजीनियरिंग, फार्मेसी और आर्किटेक्चर कोर्स में एडमिशन के लिए 24 मई को डब्ल्यूबीजेईई-2026 कराएगा। जो कैंडिडेट परीक्षा देना चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे डिटेल में जानकारी के लिए समय-समय पर बोर्ड की वेबसाइट (www.wbjeeb.nic.in/ www.wbjeeb.in) देखते रहें। जेईई बोर्ड के नए चेयरमैन गौतम पॉल ने कहा-इस साल, टेस्ट विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद होंगे। तारीखें राज्य प्रशासन के साथ बातचीत के बाद तय की गई हैं।

बोर्ड ने कहा कि सभी तारीखें टेंटेटिव हैं और ''ज़रूरत पड़ने पर बदली जा सकती हैं। जेईई बोर्ड के एक अधिकारी ने कहा कि रिज़ल्ट के पब्लिकेशन की जानकारी बाद में दी जाएगी। उन्होंने कहा-इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया ने अभी तक चुनावों का शेड्यूल अनाउंस नहीं किया है। क्योंकि मौजूदा विधानसभा का टर्म 7 मई तक है, इसलिए उम्मीद है कि चुनाव उससे पहले खत्म हो जाएंगे। अधिकारी ने कहा-इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, परीक्षा 24 मई को शेड्यूल की गई है। बोर्ड आमतौर पर बीटेक प्रोग्राम के कैंडिडेट्स से दिसंबर में एडवर्टाइज़मेंट पब्लिश होने के बाद जनवरी और फरवरी की शुरुआत के बीच ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करने के लिए कहता है।

गोताखोरों के लिए 6 करोड़ के उपकरण खरीदेगा लालबाजार

गंगा के गंदा पानी से वॉटर ड्रोन को हो रही रुकावट के चलते लिया फैसला

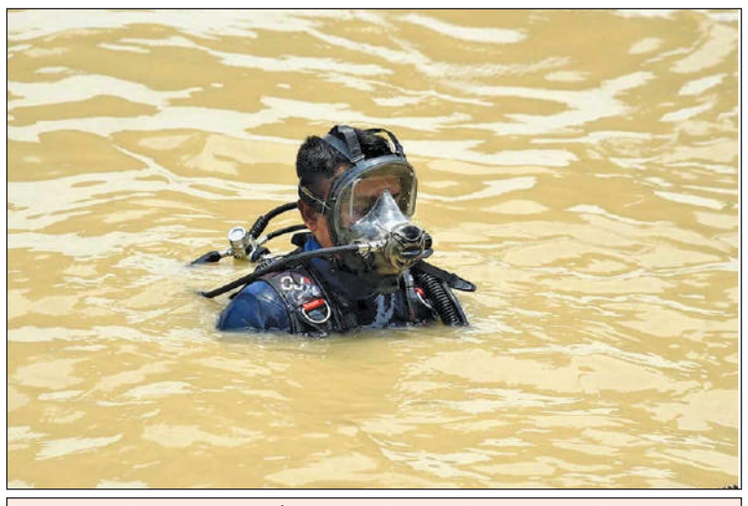

निज संवाददाता : लालबाजार (कोलकाता पुलिस मुख्यालय) अंडरवॉटर कम्युनिकेशन सिस्टम को अहमियत दे रहा है। गंगा में डूबने वाले किसी व्यक्ति को ढूंढने के लिए कोलकाता पुलिस पानी के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के गोताखोरों और ज़मीन पर उनके कंट्रोलर्स के बीच एक स्टेट-ऑफ-द-आर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम (अत्याधुनिक संचार प्रणाली) ला रही है। असल में, अगर गंगा की तलहटी में या शहर के किसी भी बड़े वॉटर बॉडी में कोई आपदा आती है, तो लालबाजार उससे निपटने के लिए करीब 6 करोड़ के मॉडर्न इक्विपमेंट (आधुनिक उपकरण) खरीद रहा है। ये उपकरण और सामान कोलकाता पुलिस के डीएमजी को सौंपे जाएंगे। गौरतलब है कि गंगा में डूबने की स्थिति में रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ-साथ गंगा की तलहटी में किसी भी आपदा या नाव के डूबने की स्थिति में भी वॉटर ड्रोन बहुत असरदार होते हैं। लेकिन पुलिस सूत्रों ने बताया कि गंगा में कई जगहों पर प्रयोग के तौर पर वॉटर ड्रोन लॉन्च किए गए थे। वे ड्रोन गंगा की सतह से कई मीटर नीचे उतरे और वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। लेकिन गंगा का गंदा पानी रुकावट डाल रहा था। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, गंगा का पानी इतना गंदा है कि ड्रोन के कैमरे में साफ इमेज (तस्वीर) नहीं आ पाई। इस वजह से, कुछ मीटर दूर क्या है, यह देखना मुमकिन नहीं था। लालबाजार के अधिकारी अभी भी इस बात को लेकर शक में हैं कि गंगा में किसी भी रेस्क्यू ऑपरेशन में वॉटर ड्रोन कितने असरदार हैं।

ऐसे में, लालबाजार के मुताबिक, अगर रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान डाइवर्स (गोताखोर) के पास एक एडवांस्ड अंडरवाटर कम्युनिकेशन सिस्टम होता तो यह और भी असरदार हो सकता था। हर सेट में, दो डाइवर्स एक-दूसरे से और गंगा या पानी की जगहों के किनारे कंट्रोलर से बात कर पाएंगे। अगर गोताखोर फुल मास्क भी पहने होंगे, तो भी कम्युनिकेशन सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं होगी। दो डाइवर्स के बीच दो अलग-अलग रंग की कम्युनिकेशन रस्सियों या केबल के ज़रिए बातचीत होगी। डाइवर्स के पास वाटरप्रूफ ईयरफोन और माइक्रोफोन सेट होंगे। पानी से बुलबुले या किसी और फालतू शोर को दूर रखने का भी सिस्टम होगा। अगर किसी डाइवर को बचाव के काम के दौरान कुछ संदिग्ध या ज़रूरी दिखता है या वह खतरे में है, तो वह दूसरे डाइवर और कंट्रोलर को यह मैसेज देगा।

लालबाजार ने कुल 24 लाख रुपए की लागत से यह अंडरवाटर कम्युनिकेशन सिस्टम खरीदने का प्लान बनाया है। इसके अलावा, गोताखोर के लिए खास मास्क और मॉडर्न कपड़े खरीदे जा रहे हैं ताकि गोताखोर लंबे समय तक पानी के अंदर रहकर अलग-अलग ऑपरेशन कर सकें। यह पक्का करने के भी इंतज़ाम हैं कि ज़हरीली गैसें आसानी से पानी के अंदर निकल सकें और गोताखोर को पानी के अंदर देखने में कोई दिक्कत न हो। लालबाजार ऐसे दस स्टेट-ऑफ-द-आर्ट डाइविंग सूट 3.15 करोड़ रुपये में खरीद रहा है।

* डाइवर की मदद करने और पानी की सतह से बचाव ऑपरेशन करने के लिए, कोलकाता पुलिस करीब 44 लाख रुपये की लागत से बीस रबर बोट खरीद रही है। हर बोट में पांच बचावकर्मियों के लिए सीटें हैं।
* डीएमजी और वॉटर पुलिस के लिए 120 चमकीले नारंगी रंग के बॉयेंसी रिंग खरीदे जा रहे हैं। हर एक की कीमत 3,000 रुपये है।
* साथ ही, बचाव काम के लिए 6 लाख रुपये की लागत से चार पैडल बोट भी खरीदी जा रही हैं। हर बोट में दो बचावकर्मियों के बैठने की जगह है।
* बचाव काम के लिए 70 लाइफ जैकेट भी लाई जा रही हैं। इसके अलावा, पानी के अंदर चीज़ों को काटने के लिए पांच खास हाइड्रोलिक कटर लाए जा रहे हैं।
* पुलिस ने बताया कि 15 लाख रुपए की कीमत वाला यह डिवाइस पानी में 25 मीटर नीचे भी डूबी हुई नावों या पानी के जहाजों को काटने में सक्षम है।

राज्य सरकार किसानों से 9.50 रुपए की दर पर खरीदेगी आलू

निज संवाददाता : विधानसभा चुनाव से पहले किसानों के हितों की रक्षा के लिए राज्य कैबिनेट ने आलू की खरीद कीमत तय की थी। राज्य के कृषि विपणन विभाग ने उस फैसले को लागू करने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक, राज्य सरकार किसानों से 9 रुपए 50 पैसे प्रति किलो के हिसाब से आलू खरीदेगी। यह खरीद प्रक्रिया फिलहाल 31 मार्च तक सरकारी मैनेजमेंट में जारी रहेगी। हालांकि, यह बताया गया है कि हालात को देखते हुए अगर ज़रूरत पड़ी तो समय सीमा को और बढ़ाया जा सकता है।सरकारी प्लान के मुताबिक, ज्योति वैरायटी के आलू खरीदने का कुल टारगेट 12 लाख टन रखा गया है। कोल्ड स्टोरेज में आलू रखने के लिए पहले से ही करीब 30 फीसदी जगह रिजर्व कर दी गई है। एक किसान सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा 35 क्विंटल यानी 70 बोरी आलू बेच सकता है। यह प्रोजेक्ट राज्य के 12 मुख्य आलू उत्पादक जिलों में लागू किया जाएगा।प्रशासन यह पक्का करेगा कि असली किसानों से तय कीमत पर आलू खरीदे जाएं। इसके लिए किसानों को बीडीओ ऑफिस में अप्लाई करना होगा।

यह सुविधा पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर दी जाएगी। एप्लीकेशन के वेरिफिकेशन के दौरान बीडीओ ऑफिस कृषकबंधु सर्टिफिकेट, बांग्ला फसल बीमा डॉक्यूमेंट, किसान क्रेडिट कार्ड और जमीन के डॉक्यूमेंट की जांच करेगा। इसके बाद संबंधित कोल्ड स्टोरेज तय किया जाएगा। किसानों की लिस्ट संबंधित कोल्ड स्टोरेज को भेजी जाएगी और बिक्री से होने वाली रकम सीधे किसान के बैंक अकाउंट में जमा कर दी जाएगी। राजनीतिक हलकों के एक हिस्से के मुताबिक, आलू पैदा करने वाले ग्रामीण इलाकों में इस कदम से सत्ताधारी पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनावों में कुछ राजनीतिक फायदा मिल सकता है। इसके अलावा, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अधिकारियों के एक हिस्से का मानना है कि इस साल आलू की अच्छी पैदावार से न सिर्फ किसानों को फायदा होगा, बल्कि आम लोगों को भी सस्ते दामों पर आलू मिल सकेगा।

दुर्घटना वाले इलाकों में राज्य सरकार नियुक्त करेगी 'पथबंधु'

निज संवाददाता : राज्य सरकार ने दुर्घटना वाले इलाकों में जल्दी बचाव और मेडिकल सेवा देने के लिए पथबंधु नियुक्त करने का प्लान बनाया है। प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक, राज्य में अलग-अलग नेशनल और स्टेट हाईवे पर पहचाने गए 1,000 से ज़्यादा एक्सीडेंट वाले इलाकों में नए पथबंधु अपॉइंट किए जा सकते हैं। प्रस्ताव के मुताबिक, हर दुर्घटना वाले इलाके में सात ट्रेंड पथबंधु नियुक्त किए जाएंगे। परिवहन विभाग के डेटा के मुताबिक, पिछले कुछ सालों में राज्य में सड़क दुर्घटना की संख्या में खतरनाक बढ़ोतरी हुई है। खासकर दुर्घटना के बाद जल्दी मदद न मिलने की वजह से घायलों की जान जाने के भी कई मामले सामने आ रहे हैं। कभी-कभी रात में हादसा होने पर स्थानीय प्रशासन तक पहुंचने में देरी होती है। नतीजतन, घायलों को हॉस्पिटल ले जाने में देरी की वजह से स्थिति और मुश्किल हो जाती है। इस स्थिति से निपटने के लिए, राज्य ने दुर्घटना वाली जगह पर तुरंत फर्स्ट एड और बचाव सेवाएं देने के लिए पथबंधु की नियुक्ति बढ़ाने की पहल की है। प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक, नए फैसले के तहत, हर दुर्घटना वाले इलाके में सात वॉलंटियर नियुक्त किए जा सकते हैं।

आमतौर पर, पथबंधु वॉलंटियर के तौर पर काम करते हैं। हालांकि, प्रशासन उनके साथनियमित तालमेल बनाए रखता है ताकि दुर्घटना होने पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने करीब पांच साल पहले पथबंधु प्रोजेक्ट शुरू किया था। उस समय हर जिले में वॉलंटियर नियुक्त किए गए थे और उनके लिए खास ट्रेनिंग का इंतज़ाम किया गया था। लेकिन हाल के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला है कि नेशनल और स्टेट हाईवे पर 1,000 से ज़्यादा दुर्घटना वाले इलाकों की पहचान की गई है। उन इलाकों में दुर्घटनाओं के ट्रेंड और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, नए पथबंधु नियुक्त करने का प्लान बनाया गया है। नियुक्त किए गए पथबंधु को एडवांस ट्रेनिंग देने के अलावा, मॉडर्न फर्स्ट एड बॉक्स देने के बारे में भी सोचा गया है। उन्हें दुर्घटना में घायल लोगों की जल्दी से पट्टी बांधने, खून बहना रोकने और इमरजेंसी में फर्स्ट एड देने की हैंड्स-ऑन ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा, हर पथबंधु को एक आइडेंटिटी कार्ड और एक स्पेशल जैकेट दी जाएगी ताकि आम लोग और एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें आसानी से पहचान सकें। हालांकि, प्रशासन के मुताबिक, पथबंधु के काम को लेकर आम लोगों में जागरूकता की कमी है। इसलिए, नए लोगों को भर्ती करने के अलावा, राज्य जन जागरण बढ़ाने के लिए भी पहल कर रहा है। पथबंधु के ज़रिए अलग-अलग इलाकों में जागरूकता कैंपेन चलाने का प्लान है ताकि दुर्घटना होने पर लोग जल्दी से उनकी मदद ले सकें।

बेटे की तलाश में बांग्लादेश गई महिला ढाई साल तक जेल में रही बंद

निज संवाददाता : यह कोई बॉलीवुड फ़िल्म नहीं। कोई कहानी नहीं। यही नहीं, मध्य वर्ग व्यक्ति की ज़िंदगी की यह घटना किसी भी स्क्रीनप्ले को मात दे देगी। एक बेबस पति बांग्लादेश में कैद अपनी पत्नी को भारत वापस लाने के लिए प्रशासन के दर-दर भटक रहा था। वह अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए सरकार से बेताब गुहार लगा रहा था। भले ही वह वैध भारतीय पहचान पत्र के साथ बांग्लादेश गया था, लेकिन उसकी पत्नी पड़ोसी देश जाकर बहुत मुश्किल में पड़ गई और फिर उसे जेल जाना पड़ा। आखिरकार, भारत-बांग्लादेश सरकारों की मदद से उसकी पत्नी फाल्गुनी रॉय चौधरी ढाई साल के लंबे समय के बाद भारत लौटीं। वह गेदे बॉर्डर के पार अपने पति प्रोसेनजीत चौधरी का हाथ थामे बनगांव के बोहलदाहा में अपने घर लौटीं। पता चला है कि प्रोसेनजीत चौधरी उत्तर 24 परगना के बनगांव थाने के बोहलदाहा इलाके के रहने वाले हैं। उनकी पत्नी फाल्गुनी रॉय भारतीय नागरिक हैं। कुछ साल पहले वह सही कागज़ात के साथ बांग्लादेश चली गई थी। प्रोसेनजीत ने बताया कि उसकी पत्नी फल्गुनी की शादी पहले बनगांव टंगरा कॉलोनी के एक आदमी से हुई थी। उनका एक बेटा भी था। बाद में फल्गुनी को पता चला कि वह आदमी बांग्लादेशी नागरिक है। तभी से उनकी शादीशुदा ज़िंदगी में झगड़ा शुरू हो गया। आरोप है कि कुछ दिनों बाद वह आदमी गैर-कानूनी तरीके से बांग्लादेश भाग गया और उनके बेटे को भी अपने साथ ले गया। युवती उसे बेटे को ले जाने से रोक नहीं पाई। फाल्गुनी अकेली रहने लगी। उसके बाद फाल्गुनी की मुलाकात बोआलदाह गांव के प्रोसेनजीत से हुई। दोनों ने शादी कर ली। 2023 में फाल्गुनी अपने बेटे को ढूंढने के लिए भारतीय पासपोर्ट और वीजा लेकर पेट्रापोल बॉर्डर के रास्ते बांग्लादेश गई। उसे उसका पति भी मिल गया। आरोप है कि पहले पक्ष के पति ने उसका पासपोर्ट और दूसरे भारतीय पहचान पत्र छीन लिए और उसे जान से मारने की धमकी दी। खतरे का सामना करते हुए, उसने प्रोसेनजीत को बताया और अपनी जान बचाने के लिए बांग्लादेश बीडीआर पहुंची। लेकिन उसके पास सही पहचान पत्र नहीं होने के कारण उसे बांग्लादेश पुलिस को सौंप दिया गया। घटना के बारे में पता चलने पर प्रोसेनजीत भी वैध वीज़ा और पासपोर्ट लेकर झेनाइदाह पहुंचे और बांग्लादेश पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। बाद में उन्हें पता चला कि फाल्गुनी जेल में है। जब उन्होंने कोर्ट में फाल्गुनी के लीगल एंट्री डॉक्यूमेंट्स दिखाए, तो बांग्लादेश कोर्ट ने सज़ा कम कर दी। यहीं से एक लंबे संघर्ष की शुरुआत हुई। लेकिन प्रोसेनजीत ने हार नहीं मानी। भारत लौटने के बाद उन्होंने फाल्गुनी को वापस लाने के लिए कई बार विदेश मंत्रालय, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसपी ऑफिस में अर्ज़ी दी। खुशकिस्मती से उनकी पत्नी भारतीय नागरिक हैं। भारत सरकार से बार-बार अपनी पत्नी को वापस लाने की गुज़ारिश करने के बाद वे निराश और प्रशासन से नाराज़ थे। आखिरकार, दोनों देशों की सरकारों और बांग्लादेश कोर्ट ने उनकी अर्ज़ी पर जवाब दिया। उनकी पत्नी को जेल से रिहा कर दिया गया। आखिरकार, ढाई साल बाद फाल्गुनी बॉर्डर पार करके घर लौट आईं। और अपनी पत्नी को अपने पास देखकर दुखी प्रोसेनजीत भी खूब रोए। सोमवार शाम को दोनों के पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने बड़ी धूमधाम से उनकी दोबारा शादी कर दी। वे एक हो गए। इलाके के लोगों को मिठाई खिलाई गई। उनकी आंखों के कोने खुशी के आंसुओं से चमक उठे।

दीघा के समुद्र की लहरों पर चलेगा आकर्षक क्रूज 'एमवी निवेदिता'

मंजूरी मिलते ही पर्यटकों के लिए शुरू होगी नई सेवा

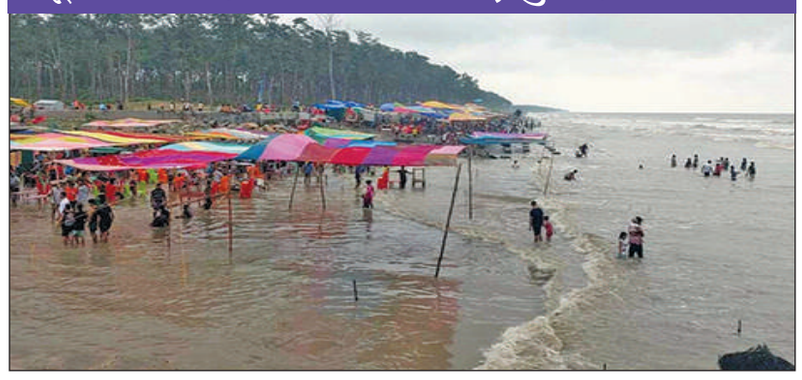

निज संवाददाता : दीघा में पर्यटकों के लिए एक नया आकर्षण शुरू होने जा रहा है। मंज़ूरी मिलते ही एमवी निवेदिता नाम का आकर्षक क्रूज़ दीघा के समुद्र में चलेगा। हालांकि, प्रशासनिक सूत्रों ने बताया है कि यह क्लियरेंस बहुत जल्द मिल जाएगा। फिलहाल, इस क्रूज़ शिप को लॉन्च करने के लिए सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। यह जहाज़ दीघा के पास पूर्व मुकुंदपुर में नायकली मंदिर के पास चंपा नहर में बनी जेट्टी पर लंगर डाले हुए है। क्लियरेंस मिलते ही यह समुद्र में तैरेगा। माना जा रहा है कि यह दीघा आने वाले टूरिस्ट के लिए आकर्षक बन जाएगा। इतना ही नहीं, टूरिस्ट के लिए कई इंतज़ाम भी हैं। दीघा-शंकरपुर डेवलपमेंट बोर्ड की पहल पर, इस क्रूज़ शिप पर टूरिस्ट के आने-जाने की सुविधा के लिए एक पोंटून जेट्टी और गैंगवे बनाया गया है। मरीन ड्राइव से सटी सड़क से जेट्टी तक एक लंबा लकड़ी का पुल बनाया गया है। पुल पर कई ट्रैफिक लाइटें लगाई गई हैं। डीएसडीए द्वारा अपॉइंट किए गए एक कॉन्ट्रैक्टर ने सभी प्लान को लागू किया है। नया क्रूज़ शिप पीपीपी (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल पर चलेगा। असल में, परिवहन विभाग का यह जहाज पहले हल्दिया से लाया गया था। फिर डीएसडीए ने टेंडर निकाला और उस कॉन्ट्रैक्टर को क्रूज शिप चलाने की ज़िम्मेदारी दी। पोंटून जेट्टी और गैंगवे बनाए गए। इसके अलावा, नहर और आस-पास के समुद्र में कई ट्रायल किए गए ताकि यह देखा जा सके कि क्रूज शिप कितना सुरक्षित है। जेट्टी तक जाने वाला रास्ता कच्चा था। सारी दिक्कतों को दूर करने के बाद, सड़क समेत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है।

इस क्रूज शिप पर क्या-क्या सुविधाएं हैं?

क्रूज शिप को रात में लाइटों से सजाया जाएगा। साउंड सिस्टम होगा। नाच-गाने और खाने-पीने समेत घूमने-फिरने की सारी सुविधाएं होंगी। इस मॉडर्न क्रूज शिप में एक छोटा रेस्टोरेंट भी है और कल्चरल प्रोग्राम भी होंगे। इस क्रूज शिप पर हर घंटे घूमने-फिरने का इंतज़ाम होगा। शुरुआत में, हर दिन दो ट्रिप तय किए गए हैं। दो डेक पर ज़्यादा से ज़्यादा 80 टूरिस्ट बैठ सकते हैं। एलईडी स्क्रीन पर दीघा की डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को डॉक्यूमेंट्री के तौर पर दिखाया जाएगा और पैसेंजर दीघा और उसके आस-पास के इलाकों के बारे में बहुत कुछ जान पाएंगे। क्रूज शिप जेट्टी से अपना सफ़र शुरू करेगा। यात्रा के आखिर में यह वहीं वापस आएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रति व्यक्ति किराया अभी तय नहीं हुआ है। इस क्रूज शिप के लिए दो तरह की बुकिंग होगी-स्पॉट और ऑनलाइन। परियोजना के जिम्मेदार कॉन्ट्रैक्टर के हेड प्रदीप दास ने कहा कि क्रूज शिप चलाने के लिए सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया गया है। जैसे ही प्रशासन से हरी झंडी मिलेगी, क्रूज शिप को लॉन्च कर दिया जाएगा। इस बीच, डीएसडीए के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुरजीत पंडित ने कहा कि जरूरी अप्रूवल न मिलने की वजह से क्रूज शिप को ऑपरेट नहीं किया जा सकता है। हमने इसे ऑपरेट करने की मंजूरी लेने के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए परिवहन विभाग में अप्लाई किया है। उम्मीद है कि जरूरी अप्रूवल मिलते ही क्रूज को जल्द ही लॉन्च कर दिया जाएगा।

गोरखालैंड की पुरानी मांग फिर चर्चा में

भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन से मिले गोरखा नेता

निज संवाददाता : देश की संघीय संरचना और राज्यों के पुनर्गठन से जुड़ा गोरखालैंड का मुद्दा एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीतिक विमर्श के केंद्र में आ गया है। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले गोरखा समुदाय के प्रतिनिधियों ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात कर अलग गोरखालैंड राज्य की पुरानी मांग दोहराई। साथ ही यह भी कहा कि यदि अलग राज्य संभव नहीं है तो उत्तर बंगाल को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया जाए।

सिलीगुड़ी में हुई इस बैठक में गोरखा समुदाय के प्रतिनिधियों ने पहाड़ी क्षेत्रों की प्रशासनिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं को विस्तार से रखा। बैठक में दार्जिलिंग से भाजपा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता राजू बिष्ट और भाजपा विधायक नीरज जिम्बा भी मौजूद थे।

बैठक के बाद सांसद राजू बिष्ट ने कहा-हर नागरिक को अपनी बात रखने का अधिकार है और गोरखा समाज की पीड़ा को सामने आना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा संवाद के जरिए समाधान में विश्वास करती है और यदि 2026 में राज्य में भाजपा की सरकार बनती है तो पहाड़ की समस्याओं का स्थायी समाधान निकाला जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि सांसद के रूप में वे गोरखा समाज के साथ मजबूती से खड़े हैं। गौरतलब है कि गोरखालैंड की मांग 1980 के दशक से राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा रही है। दार्जिलिंग और आसपास के पहाड़ी इलाकों में अलग राज्य की मांग को लेकर कई बार आंदोलन हुए। 2007 के आंदोलन के बाद गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन (जीटीए) का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय स्वशासन के जरिए समस्याओं का समाधान करना था। हालांकि, गोरखा संगठनों का आरोप है कि जीटीए के गठन के बावजूद मूल समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं।

देश में समय-समय पर नए राज्यों के गठन का इतिहास रहा है। वर्ष 2000 में उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ बने, जबकि 2014 में तेलंगाना का गठन हुआ। ऐसे में गोरखालैंड की मांग को भी समर्थक संवैधानिक दायरे में वैध राजनीतिक मांग बताते रहे हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के विभाजन के किसी भी प्रस्ताव का लगातार विरोध किया है। दार्जिलिंग लोकसभा सीट पर लंबे समय से भाजपा का वर्चस्व रहा है। पहाड़ी क्षेत्र में भाजपा को लगातार समर्थन मिलता रहा है, लेकिन अलग राज्य की मांग पूरी न होने को लेकर स्थानीय असंतोष भी समय-समय पर सामने आता रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राज्य विभाजन का मुद्दा भाजपा के लिए भी संतुलन साधने वाली चुनौती है, क्योंकि एक ओर पहाड़ की आकांक्षाएं हैं तो दूसरी ओर पूरे राज्य की राजनीतिक संवेदनशीलता। पहाड़ की स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने पहले भी वार्ता प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और मध्यस्थ नियुक्त करने की पहल की है, ताकि संवाद के जरिए समाधान का रास्ता निकाला जा सके। इसी क्रम में गोरखा नेताओं के साथ भाजपा नेतृत्व की ताजा बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि गोरखालैंड का प्रश्न केवल क्षेत्रीय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय संघीय ढांचे, पहचान की राजनीति और प्रशासनिक विकेंद्रीकरण से जुड़ा व्यापक मुद्दा है। आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि संवाद और राजनीतिक सहमति के जरिए इस लंबे समय से लंबित मांग का कोई ठोस समाधान निकल पाता है या नहीं।

केंद्र ने बंगाल में नए रेल प्रोजेक्ट को दी मंज़ूरी

निज संवाददाता : मोदी कैबिनेट ने पश्चिम बंगाल में नए रेलवे प्रोजेक्ट को मंज़ूरी दी। कैबिनेट ने दो फ़ैसले लिए हैं। इसके तहत पश्चिम बंगाल और झारखंड में रेलवे के मल्टी-ट्रैकिंग प्रोजेक्ट को मंज़ूरी दे दी गई है ताकि ट्रेन की आवाजाही का सिस्टम आसान हो सके। इसके अलावा, कोलकाता के पोर्ट एरिया में पुराने बेसक्यूल ब्रिज के रेनोवेशन के लिए भी फ़ंड अलॉट किया गया है।रेलवे दोनों राज्यों में रेलवे के मल्टी-ट्रैकिंग प्रोजेक्ट पर 4,474 करोड़ रुपये खर्च करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने इस प्रोजेक्ट को मंज़ूरी दी। पश्चिम बंगाल में इस रेलवे प्रोजेक्ट पर सैंथिया-पाकुड़ की चौथी लाइन और संतरागाछी-खड़गपुर की चौथी लाइन पर काम किया जाएगा।

रेलवे सूत्रों के मुताबिक, पूरा प्रोजेक्ट करीब 192 किमी लंबा है, जिसमें दोनों राज्यों के पांच ज़िले कवर होंगे। काम पूरा होने में पांच से छह साल लगेंगे। दावा है कि इससे 5,652 ग्रामीण इलाकों में रेलवे कम्युनिकेशन सिस्टम आसान हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट में न सिर्फ पैसेंजर ट्रेन का आना-जाना आसान होगा, बल्कि मिनरल समेत कई तरह के सामानों की ट्रांसपोर्टेशन भी आसान होगी। हर साल करीब 31 मिलियन टन ज़्यादा सामान ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा।

गंगा नदी पर जल्द शुरू होगी वॉटर मेट्रो

कोच्चि की कंपनी के साथ जल्द मीटिंग करेगा कोलकाता नगर निगम

निज संवाददाता : राज्य सरकार ने वॉटरवे ट्रांसपोर्ट को और आधुनिक और तेज़ बनाने के लिए गंगा में वॉटर मेट्रो शुरू करने की पहल की है। सरकार केरल के कोच्चि की एक कंपनी की मदद से इस प्रोजेक्ट को लागू करने की संभावना तलाश रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस बारे में अगले हफ़्ते कोलकाता नगर निगम में एक ज़रूरी मीटिंग होने वाली है। वहां कोच्चि के वॉटर मेट्रो प्रोजेक्ट का डेलीगेशन अपने प्लान के बारे में डिटेल देगा। नगर निगम के सूत्रों के मुताबिक, कोच्चि की तरह कोलकाता में भी स्टेट-ऑफ़-द-आर्ट बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक हाइब्रिड बोट इस्तेमाल करने का प्रपोज़ल है। ये वॉटरक्राफ्ट एनवायरनमेंट-फ्रेंडली (पर्यावरण-अनुकूल) होंगे और तेज़ सफ़र को आसान बनाएंगे। संबंधित कंपनी ने भी भरोसा दिलाया है कि गंगा के एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना यह सर्विस कैसे दी जा सकती है। प्रासशनिक सूत्रों के मुताबिक, अगर यह नई वॉटर मेट्रो शुरू होती है तो शहर की सड़कों पर ट्रैफ़िक की भीड़ को काफ़ी हद तक कम किया जा सकेगा। यह भी माना जा रहा है कि यह पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में भी अहम रोल निभाएगी। गंगा जलमार्ग का इस्तेमाल करके यात्री कम समय में शहर के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच सकेंगे। अगले हफ़्ते होने वाली मीटिंग में कोच्चि वॉटर मेट्रो अधिकारियों के सामने राज्य सरकार का बयान भी पेश किया जाएगा। किस तरह की नावें बनेंगी, प्रोजेक्ट की संभावित लागत क्या है और सर्विस लॉन्च की रूपरेखा क्या होगी-इन सभी मुद्दों पर उस दिन विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद है।

गौरतलब है कि कोच्चि वॉटर मेट्रो देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड फेरी-बेस्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम (एकीकृत नौका-आधारित सार्वजनिक परिवहन प्रणाली) है। यह सर्विस केरल के कोच्चि शहर के 10 द्वीपों को मुख्य भूमि से जोड़ती है। ये पूरी तरह से एयर-कंडीशन्ड नावें बैटरी और डीज़ल जनरेटर से चलने वाली हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर चलती हैं और पर्यावरण के अनुकूल मानी जाती हैं। इत्तेफ़ाक से, देश में पहली मेट्रो सर्विस कोलकाता में शुरू की गई है। कोलकाता की शान मेट्रो हर दिन लाखों यात्रियों को लेकर चलती है। इसी सिलसिले में, इस बार वॉटरवे ट्रांसपोर्ट को भी मॉडर्न बनाने का प्लान बनाया गया है। नबान्न में शीर्ष अधिकारियों का एक समूह मानता है कि अगर वॉटर मेट्रो शुरू हो जाती है, तो कोलकाता सबवे की तरह शहर के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक नया डायमेंशन जुड़ सकता है।

एसएसकेएम अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम में एसिड पीड़िताओं ने लिया संकल्प

'आत्मनिर्भर बनना है लक्ष्य'

निज संवाददाता : चेहरे जल जाने के बाद भी वे हार मानने को तैयार नहीं हैं! जले हुए चेहरों के साथ ज़िंदा रहने की लड़ाई जारी है। कोई कपड़े सिल रहा है। किसी ने रोल की दुकान खोल ली है। सुनीता दत्ता, तुसी मंडल का लक्ष्य आत्मनिर्भर बनना है। लक्ष्मी भंडार पर सबका भरोसा है। उनके शब्दों में-इस लड़ाई में सबसे बड़ा भरोसा ममता बनर्जी के लक्ष्मी भंडार पर है। एसिड पीड़िता पॉली देबनाथ के लिए एसएसकेएम हॉस्पिटल के इंस्टीट्यूट ऑफ़ साइकेट्री के साइकोलॉजिकल सोशल वर्क डिपार्टमेंट और एक फाउंडेशन ने एक खास प्रोग्राम किया। 'हीलिंग, डिग्निटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ़ एसिड विक्टिम्स' (एसिड पीड़ितों का उपचार, सम्मान और सशक्तिकरण) नाम के प्रोग्राम में एसिड पीड़ित युवा लड़कियां आईं। इस कार्यक्रम में एसिड पीड़िताओं ने आत्मनिर्भर बनने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि यही उनका मुख्य लक्ष्य है। उन्होंने कहा-लड़ाई मुश्किल है।लेकिन नामुमकिन नहीं। चेहरे पर एसिड से जलन और बाहरी नुकसान। कोई उन्हें आसानी से नौकरी पर नहीं रखना चाहता। बच्चों की देखभाल करने वाली दाई की नौकरी? यह भी नहीं मिलेगी। कारण, बच्चा डरेगा। इसी वजह से घरेलू काम करने वाली का काम नहीं मिल रहा है। फिर भी वे लगातार लड़ रही हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लक्ष्मी भंडार ने उनकी मज़बूत इच्छाशक्ति को ऑक्सीजन दी है। पोली देबनाथ इससे बच्चों के कपड़े सिलती हैं। नदिया जिले के राणाघाट की रहने वाली पोली के चेहरे पर 2014 में एसिड फेंका गया था। इसके पीछे की वजह क्या थी? पड़ोस के एक लड़के ने उसे प्रपोज़ किया। उसने मना कर दिया, लेकिन उसने उसके चेहरे पर एसिड फेंक दिया। पोली ने कहा-इस घटना के बाद, उसके पति ने भी उसे छोड़ दिया। इच्छापुर की सुनीता दत्ता ने कहा कि 2010 में, एक हमलावर ने प्रपोज़ल को मना करने पर उस पर एसिड फेंका। फिर? पच्चीस सर्जरी हुईं। उसका एसएसकेएम हॉस्पिटल में लंबे समय से इलाज चल रहा है। वह अब शादीशुदा है। तुसी मंडल ने भी अपना संघर्ष जारी रखा है। सत्ताईस साल की तुसी 2016 में एसिड अटैक की शिकार हुई थी। उस समय वह 12वीं क्लास की छात्रा थी। कैनिंग की रहने वाली तुसी के शब्दों में-स्कूल जाते समय कुछ लड़के लड़कियों को ताना मारते थे। मैंने उस घटना का विरोध किया। बदला लेने के लिए मैंने उसके चेहरे पर एसिड फेंक दिया। अब तुसी घर पर मुर्गी पालन कर गुजारा करने की कोशिश कर रही है। उसकी बड़ी उम्मीद लक्ष्मी भंडार है। एसएसकेएम अस्पताल के मनोरोग संस्थान में कार्यक्रम के उद्घाटन के मौके पर निदेशक मणिमय बनर्जी, स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त निदेशक सुब्रत रॉय, मनोरोग संस्थान के डॉ. सुजीत सरखेल, स्वास्थ्य शिक्षा के संयुक्त निदेशक डॉ. कौशिक कर, मनोवैज्ञानिक सामाजिक कार्य विभाग के प्रमुख मयंक कुमार मौजूद थे। डॉ. मणिमय बनर्जी ने कहा कि एसिड अटैक एक सामाजिक समस्या है। कार्यक्रम में महिला शिकायत प्रकोष्ठ की ओसी इंस्पेक्टर सोफिया मल्लिक मौजूद थीं।

रवींद्र सरोवर आइलैंड्स में पेड़ लगाएगा केएमडीए

- इलाके में पक्षियों का बसेरा फिर से बसाना लक्ष्य

निज संवाददाता : राज्य के शहरी विकास विभाग ने रवींद्र सरोवर में फैले आइलैंड्स पर नए पेड़ लगाने का फैसला किया है ताकि इलाके में पक्षियों के घोंसले फिर से बन सकें। इन द्वीपों पर मौजूद कई पेड़ सड़ रहे हैं और दूर से बेजान दिखते हैं। ज़्यादातर पेड़ बिना पत्तों के खड़े हैं, जिससे हरियाली कम हो रही है। नए पेड़ लगाने के साथ-साथ, अधिकारी आइलैंड्स के कटाव को रोकने के लिए भी कदम उठाने की योजना बना रहे हैं। इस पहल का मकसद हरियाली को वापस लाना, द्वीपों की इकोलॉजी की रक्षा करना और पक्षियों के घोंसले बनाने के लिए ज़्यादा सही जगह बनाकर उन्हें वापस खींचना है। रवींद्र सरोवर के कस्टोडियन, कोलकाता मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (केएमडीए) के एक अधिकारी ने कहा-हमने राज्य के बागवानी विभाग के विशेषज्ञों से उन प्रजातियों की पहचान करने के लिए राय मांगी है जो झील के द्वीपों के लिए सही होंगी ताकि ज़्यादा पक्षी आ सकें और पेड़ों पर घोंसला बना सकें। केएमडीए राज्य के शहरी विकास विभाग के तहत काम करता है। अधिकारी ने कहा-द्वीपों का ग्रीन कवर कम हो गया है, और हम इसे फिर से बनाना चाहते हैं। हम कटाव को रोकने की भी कोशिश करेंगे। पक्षी-प्रेमी और पक्षी-विज्ञानी ने कहा कि नए पौधे लगाना अच्छा है, लेकिन सूखे पेड़ों को नहीं हटाया जाना चाहिए। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के पूर्व डायरेक्टर और ऑर्निथोलॉजिस्ट असद रहमानी ने कहा-सूखे पेड़ों को बिना छेड़े रखना सबसे अच्छा है। नए पौधे लगाए जाने चाहिए। मेरा सुझाव है कि पौधे लगाते समय लोकल पेड़ों को चुना जाए।

चार दशकों से पक्षी प्रेमी रहे सुजन चटर्जी ने कहा कि पौधे बहुत सावधानी से लगाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा-जगह पर कम से कम परेशानी होनी चाहिए। यहां तक कि झाड़ियों को भी नहीं छेड़ना चाहिए। अधिकारियों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पक्षियों की बीट नए पौधों पर गिर सकती है और उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। विशेषज्ञों ने कहा कि पक्षियों की बीट एसिडिक होती है और कुछ समय बाद पेड़ों को नुकसान पहुंचाती है। चटर्जी ने कहा-नए पौधों को बचाना चाहिए और बढ़ने में मदद करनी चाहिए। नहीं तो, वे ज़िंदा नहीं रहेंगे। केएमडीए अधिकारियों ने कहा कि नए पौधे इकोसिस्टम (पारिस्थितिकी तंत्र) को बिना नुकसान पहुंचाए लगाए जाएंगे और यह पक्का किया जाएगा कि पक्षियों को कोई परेशानी या खतरा महसूस न हो।

अधिकारी ने कहा-आइलैंड्स के कटाव वाले बेस पर भी मरम्मत का काम इकोलॉजिकल (पारिस्थितिक) चिंताओं को ध्यान में रखकर किया जाएगा। अलग-अलग आइलैंड्स में अलग-अलग लेवल का कटाव हो रहा है। रवींद्र सरोवर के आइलैंड्स में रहने वाले पक्षियों में ग्रे हेरॉन, नाइट हेरॉन और कॉमोरेंट शामिल हैं।

केएमडीए ने पेड़ों और मिट्टी की मौजूदा हालत और कटाव की हद का शुरुआती सर्वे करने के बाद आइलैंड्स पर ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए एक डिटेल्ड प्लान बनाया है। मालूम हो कि रवींद्र सरोबर 193 एकड़ में फैला है। कुल एरिया का लगभग 38 फीसदी हिस्सा (लगभग 73 एकड़) वॉटर बॉडीज़ हैं।

शहरी विकास विभाग के वरिष्ठि अधिकारियों ने कहा कि फोकस मुख्य रूप से दो आइलैंड पर है, एक का साइज़ लगभग 2,600 स्क्वायर मीटर और दूसरा, लगभग 2,300 स्क्वायर मीटर का है। लेक गार्डन्स की रहने वाली और सुबह की सैर करने वाली संगीता मित्रा ने कहा-पेड़ दूर से ग्रे दिखते हैं और उन पर मुश्किल से ही कोई पत्तियां होती हैं। सुबह के समय आइलैंड का नज़ारा आंखों को अच्छा नहीं लगता।

हल करो हीरो बनो का उत्तर

1. सांप, 2.गामा किरणें, 3.नमक कर, 4.विस्थापन, 5. न्यूटन का पहला नियम

संपादकीय

इच्छामृत्यु पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

भारत यूथेनेशिया यानी इच्छामृत्यु पर धीरे-धीरे आगे बढ़ा है। अलग-अलग जागरूकता और अलग-अलग सामाजिक-आर्थिक हालात वाले देश में, जहां अलग-अलग ज़रूरतें हैं, और कई धर्म हैं, शायद इसकी उम्मीद भी थी। लेकिन 11 मार्च, 2026 को, सुप्रीम कोर्ट ने 32 साल के हरीश राणा को पैसिव यूथेनेशिया (लाइफ सपोर्ट हटाना और रोकना) देने की अपील मान ली, जो 13 साल से परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट (स्थायी वनस्पति अवस्था) में है। ऐसा भारत में पहली बार हुआ है। इससे पहले 2011 में अरुणा शानबाग केस में, कोर्ट ने कथित तौर पर शानबाग के लिए एक्टिव यूथेनेशिया (सक्रिय इच्छामृत्यु) की अपील खारिज कर दी थी, जो सालों से वेजिटेटिव स्टेट में थी। एक्टिव यूथेनेशिया को असिस्टेड सुसाइड (सहायता प्राप्त आत्महत्या) भी कहा जाता है। इसके बजाय, सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया के लिए गाइडलाइन तय कीं। दो विधि आयोग ने इस मामले पर विचार किया था। दूसरा 2012 में, इसने गाइडलाइन को और सख्त कर दिया था। आखिरकार 2018 में, सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया के लिए विस्तृत दिशानिर्देश तय कीं, जब उसने संविधान के आर्टिकल 21 के तहत सम्मान के साथ मरने के अधिकार को एक फंडामेंटल राइट (मौलिक अधिकार) माना। यह एक बहुत पहले की याचिका के जवाब में था, जिसे एक ग़ैर सरकारी संगठन, 'कॉमन कॉज़' ने दायर किया था। इस फैसले का सबसे ज़रूरी पहलू सम्मान पर ज़ोर देना है। जिस हॉस्पिटल में हरहीश राणा का लाइफ सपोर्ट हटाया जाएगा, उसे मरीज़ की परेशानी को रोकने और उसकी इज़्ज़त बनाए रखने के लिए लक्षणों को मैनेज करने का निर्देश दिया गया है। बिना किसी समझ के, मशीनों और न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन (पोषण और जलयोजन) के कृत्रिम तरीकों पर निर्भर, एक इंसान के सम्मान का दुखद नुकसान है। पैसिव यूथेनेशिया से, इस असहनीय बेइज़्ज़ती को ठीक किया जा सकता है। इसलिए यह सच में एक स्वागत योग्य फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को यह भी निर्देश दिया है कि वे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को 2018 की गाइडलाइंस के बारे में बताएं, ताकि हॉस्पिटल उन्हें बता सकें कि जब प्राइमरी और सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड गाइडलाइंस के अनुसारकिसी मरीज़ की पैसिव यूथेनेशिया के बारे में अपने फैसले पर एकमत हों। इससे पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि यह ज़रूरत बड़े पैमाने पर हो सकती है। यह दुख की बात है कि बहुत से लोग इस प्रोग्रेसिव फैसले का फायदा नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि भारत में कोर्ट तक पहुंच और जागरूकता एक जैसी नहीं है। लेकिन प्रगति धीरे-धीरे हो रही है। यह ध्यान देने वाली बात है कि कोर्ट के बार-बार कहने के बावजूद विधान मंडल ने यूथेनेशिया के बारे में कोई कानून नहीं बनाया है। कानून गाइडलाइंस से अलग होता है। फिर भी दुनिया के कई हिस्सों में यूथेनेशिया लीगल है अक्सर तब जब कोई मरीज़ ऐसी हालत में हो जहां से उसे ठीक नहीं किया जा सकता और वह इज़्ज़त से मरना चाहता हो। हालांकि यह सिर्फ सख्त रेगुलेटरी (विनियामक) शर्तों के तहत होता है। उदाहरण के लिए, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, लक्ज़मबर्ग, कनाडा या कोलंबिया, या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ़ अमेरिका के कुछ राज्य यूथेनेशिया की इजाज़त देते हैं, हालांकि हर देश में इस एक्ट की कानूनी परिभाषा और शर्तें अलग हो सकती हैं। अब समय आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के साथ पैसिव यूथेनेशिया की इजाज़त देने वाला कानून बनाया जाए।

जेडीयू में निशांत की एंट्री परिवारवाद या सियासी जरूरत?

बिहार की राजनीति में शुरू हुई एक नई बहस

निशांत कुमार का राजनीतिक सफर अभी शुरू हुआ है। यह कहना जल्दबाजी होगी कि वे अपने पिता की विरासत संभाल पाएंगे या नहीं। लेकिन इतना तय है कि उनकी एंट्री ने बिहार की राजनीति में एक नई बहस और नई प्रतीक्षा जरूर पैदा कर दी है। आने वाले वर्षों में यह साफ होगा कि यह कदम जेडीयू को स्थिरता देगा या पार्टी को एक नए संघर्ष के दौर में ले जाएगा।

अजय कुमार

बिहार की राजनीति में कभी-कभी ऐसे मोड़ आते हैं जो केवल एक व्यक्ति की एंट्री नहीं, बल्कि पूरे राजनीतिक ढांचे की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। जनता दल यूनाइटेड में निशांत कुमार का औपचारिक प्रवेश भी ऐसा ही एक क्षण है। लंबे समय तक राजनीति से दूरी बनाए रखने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे का पार्टी की सदस्यता लेना महज पारिवारिक घटना नहीं है, बल्कि उस राजनीतिक युग के अंत और दूसरे युग की शुरुआत का संकेत भी माना जा रहा है जिसमें जेडीयू की पहचान पूरी तरह नीतीश कुमार के व्यक्तित्व से जुड़ी रही है। करीब दो दशकों तक बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार निर्णायक भूमिका में रहे। 2005 में जब उन्होंने सत्ता संभाली तो राज्य की पहचान अव्यवस्था, अपराध और कमजोर बुनियादी ढांचे से जुड़ी हुई थी। उसके बाद सड़क, बिजली, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में कई योजनाएं लागू की गईं। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण, साइकिल योजना और छात्रवृत्ति कार्यक्रम जैसे फैसलों ने उन्हें ''सुशासन बाबू'' की छवि दी। 2010 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने 115 सीटें जीतकर अपने राजनीतिक चरम को छुआ था। लेकिन समय के साथ समीकरण बदले। 2020 के चुनाव में पार्टी 4345 सीटों तक सिमट गई। हालांकि 2025 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने लगभग 85 सीटें जीतकर वापसी की, फिर भी यह स्पष्ट हो गया कि पार्टी की ताकत अब पहले जैसी नहीं रही। इसी पृष्ठभूमि में निशांत कुमार का राजनीति में आना महत्व रखता है। 40 वर्ष के इंजीनियर निशांत अब तक सार्वजनिक जीवन से दूर रहे। उनका स्वभाव अंतर्मुखी बताया जाता रहा है और वे लंबे समय तक आध्यात्मिक रुचियों में व्यस्त रहने के कारण भी चर्चा में रहे। ऐसे व्यक्ति का अचानक सक्रिय राजनीति में उतरना स्वाभाविक रूप से जिज्ञासा और संदेह दोनों पैदा करता है। लेकिन राजनीति में अक्सर परिस्थितियां व्यक्ति को आगे धकेल देती हैं। जेडीयू भी उसी दौर से गुजर रही है जहां संगठन को भविष्य का चेहरा चाहिए। बिहार की राजनीति में क्षेत्रीय दलों का अनुभव बताता है कि जब कोई पार्टी लंबे समय तक एक नेता पर निर्भर रहती है तो उसके बाद नेतृत्व का संकट पैदा हो जाता है। राष्ट्रीय जनता दल में लालू प्रसाद यादव के बाद तेजस्वी यादव का उभार इसी कारण हुआ। समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश यादव का नेतृत्व सामने आया। तमिलनाडु में करुणानिधि के बाद एम.के. स्टालिन ने पार्टी संभाली। इन उदाहरणों से यह भी स्पष्ट है कि पारिवारिक उत्तराधिकार भारतीय राजनीति की एक स्वीकृत वास्तविकता बन चुका है। यही वजह है कि नीतीश कुमार, जो वर्षों तक परिवारवाद की आलोचना करते रहे, अंततः उसी रास्ते पर चलते दिखाई दिए। जेडीयू का सामाजिक आधार भी इस निर्णय को समझने में मदद करता है। पार्टी की ताकत मुख्यतः कुर्मी, कोइरी और अति पिछड़ा वर्ग के वोटों पर टिकी रही है। 2010 के चुनाव में जेडीयू-भाजपा गठबंधन को लगभग 39 प्रतिशत वोट मिले थे, जिसमें जेडीयू का बड़ा हिस्सा इन वर्गों से आया। लेकिन पिछले कुछ चुनावों में यह आधार धीरे-धीरे खिसकने लगा। भाजपा का प्रभाव बढ़ा और कई इलाकों में उसका संगठन जेडीयू से ज्यादा मजबूत होता गया। राजनीतिक विश्लेषण बताते हैं कि बिहार में भाजपा का वोट प्रतिशत 2010 के लगभग 1617 प्रतिशत से बढ़कर हाल के वर्षों में 25 प्रतिशत के आसपास पहुंच गया है। ऐसे में जेडीयू के सामने दोहरी चुनौती है अपना सामाजिक आधार बचाना और गठबंधन की राजनीति में अपनी पहचान बनाए रखना। यहीं पर निशांत कुमार की भूमिका अहम हो सकती है। जेडीयू के भीतर यह धारणा बन रही है कि अगर पार्टी के पास नीतीश कुमार के परिवार से कोई चेहरा रहेगा तो संगठन में एकजुटता बनी रहेगी। क्षेत्रीय दलों के इतिहास में यह अक्सर देखा गया है कि करिश्माई नेता के बाद पार्टी बिखर जाती है। बिहार में भी कई छोटे दल इसी कारण खत्म हो गए। इसलिए जेडीयू के नेताओं को लगता है कि निशांत की मौजूदगी कम से कम पार्टी को एक धुरी दे सकती है।हालांकि चुनौतियां कम नहीं हैं। बिहार की राजनीति में गठबंधन की प्रकृति बेहद जटिल है। भाजपा और जेडीयू का रिश्ता पिछले डेढ़ दशक में कई बार टूटा और जुड़ा है। 2013 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को लेकर दोनों दल अलग हुए। 2017 में फिर साथ आए। 2022 में जेडीयू ने महागठबंधन का रास्ता चुना और 2024 में एक बार फिर एनडीए में लौट आई। इन उतार-चढ़ावों ने जेडीयू के कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के बीच भी असमंजस पैदा किया। अगर भविष्य में भाजपा बिहार में अपना मुख्यमंत्री चेहरा आगे बढ़ाती है तो जेडीयू का राजनीतिक महत्व और घट सकता है। निशांत कुमार को इसी परिस्थिति में अपनी पहचान बनानी होगी। उनके सामने पहला काम संगठन को मजबूत करना होगा। जेडीयू के पास आज भी कई अनुभवी नेता हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश की पहचान क्षेत्रीय स्तर तक सीमित है। यदि युवा नेतृत्व को आगे लाकर संगठन में नई ऊर्जा भरी जाती है तो पार्टी को लाभ हो सकता है। बताया जा रहा है कि युवा विधायकों और करीबी सहयोगियों की एक टीम पहले से तैयार की जा रही है जो राजनीतिक प्रशिक्षण और रणनीति में निशांत की मदद करेगी। इतिहास बताता है कि राजनीति में शुरुआती छवि अंतिम नहीं होती। ओडिशा के नवीन पटनायक इसका उदाहरण हैं। 1997 में जब वे राजनीति में आए थे तो उन्हें भी अनुभवहीन और संकोची कहा जाता था। लेकिन कुछ ही वर्षों में उन्होंने अपनी शैली विकसित की और 24 साल तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे। बिहार की परिस्थितियां अलग जरूर हैं, पर यह भी सच है कि राजनीति में धैर्य और समय बहुत कुछ बदल देते हैं। फिलहाल निशांत कुमार के सामने सबसे बड़ी कसौटी यही है कि वे खुद को केवल ''नीतीश कुमार के बेटे'' से आगे साबित करें। अगर वे संगठन में संवाद बढ़ा सके, सामाजिक आधार को मजबूत कर सके और गठबंधन की राजनीति में संतुलन बना सके तो जेडीयू को नई दिशा मिल सकती है। लेकिन अगर वे केवल प्रतीकात्मक नेता बनकर रह गए तो पार्टी के भीतर खींचतान बढ़ना तय है। बिहार की राजनीति हमेशा व्यक्तित्वों के इर्द-गिर्द घूमती रही है। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और अब तेजस्वी यादव इन सभी ने अपने-अपने दौर में राज्य की राजनीति को दिशा दी है। निशांत कुमार का राजनीतिक सफर अभी शुरू हुआ है। यह कहना जल्दबाजी होगी कि वे अपने पिता की विरासत संभाल पाएंगे या नहीं। लेकिन इतना तय है कि उनकी एंट्री ने बिहार की राजनीति में एक नई बहस और नई प्रतीक्षा जरूर पैदा कर दी है। आने वाले वर्षों में यह साफ होगा कि यह कदम जेडीयू को स्थिरता देगा या पार्टी को एक नए संघर्ष के दौर में ले जाएगा।

जानें अपना राशिफल

मेष

इच्छापूर्ण समय हो सकता है इसलिए जो भी काम कर रहे हैं फायदा अवश्य होगा, अचानक धन लाभ भी हो सकता है, जीवनसाथी पूरा साथ दे सकते हैं, मन शान्त रखें।

वृषभ

शान्तिपूर्ण समय हो सकता है, कोई बहुत दिनों से रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है, किसी पर भरोसा करके काम करने की आवश्यकता है, कोई अधुरा काम पूरा हो सकता है।

मिथुन

मनोरंजन वाला समय हो सकता है, कोई रुका हुआ मांगलिक कार्य पूरा हो सकता है प्रयास करे, किसी नये व्यक्ति से काम आगे बढ़ सकता है, मन प्रसन्न रहेगा।

कर्क

मेल–मिलाप वाला समय हो सकता है इसलिए जो भी काम कर रहे हैं फायदा अवश्य होगा, कोई पुराने मित्र काम आ सकते हैं, परिवार के लोग पूरा साथ दे सकते हैं, मन में उत्साह रहेगा।

सिंह

हानिकारक समय हो सकता है इसलिए शान्ति से दिन व्यतीत करने की आवश्यकता है, किसी के बहकावे में आने से बनता काम बिगड़ सकता है, मन वश में रखें।

कन्या

लेनदेन वाला समय हो सकता है इसलिए पूरी सावधानी से काम करने की आवश्यकता है, किसी के बहकावे में आने से नुकसान भी हो सकता है, परिवार के लोग परेशान कर सकते हैं, मन स्थिर रखें।

तुला

ताकतवर समय हो सकता है इसलिए जो भी काम कर रहे हैं फायदा अवश्य होगा, कोई रुका हुआ जमीन का काम आगे बढ़ सकता है, परिवार के लोग पूरा साथ दे सकते हैं, मन में उत्साह रहेगा।

वृश्चिक

भावुकता भरा समय हो सकता है, कोई परिवार का सदस्य आपका फायदा उठा सकते हैं सावधानी रखें, किसी के बहकावे में आने से बचने की जरूरत है, मन चंचल रहेगा।

धनु

प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला समय हो सकता है, कोई बहुत दिनों से रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है जो फायदेमंद होगा, किसी अन्य व्यक्ति से काम करने पर फायदा भी हो सकता है, मन स्थिर रखे।

मकर

सहमति भरा समय हो सकता है, कोई विदेश में काम करने पर विचार हो सकता है जो फायदेमंद होगा, किसी पर भरोसा करके काम करने की आवश्यकता है, मन में संतोष रखें।

कुंभ

लापरवाही वाला समय हो सकता है इसलिए सिर्फ काम करने पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, कोई अन्य व्यक्ति आपका काम बिगाड़ सकता है सावधान रहें, आपसी प्रेम बनाये रखें, मन शान्त रखें।

मीन

समझदारी दिखाने वाला समय हो सकता है, किसी परिवार के सदस्य से मतभेद भी हो सकता है, किसी पर ज्यादा भरोसा करने से नुकसान भी हो सकता है, मन शान्त रखें।

बहुत समय पहले की बात है , एक वृद्ध सन्यासी हिमालय की पहाड़ियों में कहीं रहता था। वह बड़ा ज्ञानी था और उसकी बुद्धिमत्ता की ख्याति दूर-दूर तक फैली थी। एक दिन एक औरत उसके पास पहुंची और अपना दुखड़ा रोने लगी, बाबा, मेरा पति मुझसे बहुत प्रेम करता था, लेकिन वह जबसे युद्ध से लौटा है ठीक से बात तक नहीं करता। युद्ध लोगों के साथ ऐसा ही करता है, सन्यासी बोला।

लोग कहते हैं कि आपकी दी हुई जड़ी-बूटी इंसान में फिर से प्रेम उत्पन्न कर सकती है, कृपया आप मुझे वो जड़ी-बूटी दे दें। महिला ने विनती की।

सन्यासी ने कुछ सोचा और फिर बोला, देवी मैं तुम्हे वह जड़ी-बूटी ज़रूर दे देता लेकिन उसे बनाने के लिए एक ऐसी चीज चाहिए जो मेरे पास नहीं है। आपको क्या चाहिए मुझे बताइए मैं लेकर आउंगी, महिला बोली। मुझे बाघ की मूंछ का एक बाल चाहिए, सन्यासी बोला। अगले ही दिन महिला बाघ की तलाश में जंगल में निकल पड़ी, बहुत खोजने के बाद उसे नदी के किनारे एक बाघ दिखा, बाघ उसे देखते ही दहाड़ा, महिला सहम गयी और तेजी से वापस चली गयी। अगले कुछ दिनों तक यही हुआ, महिला हिम्मत कर के उस बाघ के पास पहुँचती और डर कर वापस चली जाती। महीना बीतते-बीतते बाघ को महिला की मौजूदगी की आदत पड़ गयी, और अब वह उसे देख कर सामान्य ही रहता। अब तो महिला बाघ के लिए मांस भी लाने लगी, और बाघ बड़े चाव से उसे खाता। उनकी दोस्ती बढ़ने लगी और अब महिला बाघ को थपथपाने भी लगी। और देखते देखते एक दिन वो भी आ गया जब उसने हिम्मत दिखाते हुए बाघ की मूंछ का एक बाल भी निकाल लिया। फिर क्या था, वह बिना देरी किये सन्यासी के पास पहुंची, और बोली, मैं बाल ले आई बाबा। बहुत अच्छे और ऐसा कहते हुए सन्यासी ने बाल को जलती हुई आग में फ़ेंक दिया अरे ये क्या बाबा, आप नहीं जानते इस बाल को लाने के लिए मैंने कितने प्रयत्न किये और आपने इसे जला दिया अब मेरी जड़ी-बूटी कैसे बनेगी? महिला घबराते हुए बोली।

अब तुम्हे किसी जड़ी-बूटी की ज़रुरत नहीं है, सन्यासी बोला जरा सोचो तुमने बाघ को किस तरह अपने वश में किया। जब एक हिंसक पशु को धैर्य और प्रेम से जीता जा सकता है तो क्या एक इंसान को नहीं? जाओ जिस तरह तुमने बाघ को अपना मित्र बना लिया उसी तरह अपने पति के अन्दर प्रेम भाव जागृत करो, महिला सन्यासी की बात समझ गयी, अब उसे उसकी जड़ी-बूटी मिल चुकी थी।

बदसूरत ऊँट

एक ऊँट था। दूसरों की निंदा करने की उसकी बुरी आदत थी। वह हमेशा दूसरे जानवरों व चिड़ियों की शक्ल-सूरत की खिल्ली उड़ाता रहता था। उसके मुँह से कभी किसी जानवर की तारीफ नही निकलती थी। गाय से वह कहता, ''जरा अपनी शक्ल तो देखो! कितनी बदसूरत हो तुम! हड्डियो का ढ़ाँचा मात्र है तुम्हारा शरीर। लगता है तुम्हारी हड्डियाँ खाल फाड़कर किसी भी क्षण बाहर निकल आएँगी।''भैंस से वह कहता, ''तुमनें तो विधाता के साथ जरुर कोई शैतानी की होगी! तभी तो उसने तुझे काली-कलूटी बनाया है। तुम्हारे टेढ़े-मेढ़े सींग तुम्हें और भी बद्सूरत बना देते है।'' हाथी को चिढ़ाता हुआ वह कहता, ''तुम तो सभी जानवरों में कार्टून जैसे दिखते हो। विधाता ने मजाक के क्षणो में तुम्हे बनाया होगा। तुम्हारे शरीर के अंगों में किसी प्रकार का संतुलन नहीं है। तुम्हारा शरीर कितना विशाल है और पूँछ कितनी छोटी! तुम्हारी आँखें कितनी छोटी हैं और कान इतने बड़े सूप जैसे। तुम्हारी सूँड़, पैर और शरीर के अन्य अंगों के बारे में तो मैं बस चुप रहूँ, यही ठीक रहेगा।'' तोते से वह कहता, ''तुम्हारी टेढ़ी और लाल रंग की चोंच बनाकर विधाता ने वाकई तुम्हारे साथ मजाक किया है।'' इस तरह ऊँट हमेशा हर जानवर की खिल्ली उडाता रहता था। एक बार ऊँट की मुलाकात एक लोमड़ी से हो गई। वह बड़ी ही मुँहफट थी और किसी को भी खरी बात सुनानें से नही हिचकती थी। ऊँट उसके बारे में उल्टा-सीधा बोलना शुरु करे, इसके पहले ही लोमड़ी नें कहा, ''अरे ऊँट, तू लोगों के बारे में उल्टी-सीधी बातें करने की अपनी गंदी आदत छोड़ दे। जरा अपनी शक्ल-सूरत तो देख। तुम्हारा लंबा चेहरा, पत्थर जैसी तुम्हारी आँखें, पीले-पीले गंदे दाँत, टेढ़े-मेढ़े भद्दे पैर और तुम्हारी पीठ पर यह भद्दा सा कूबड़। सभी जानवरों में सबसे बदसूरत तू ही है। दूसरे जानवरो में तो एक-दो खामियाँ है। पर तुम में तो बस खामियाँ ही खामियाँ हैं।'' लोमड़ी की खरी-खरी बात सुनकर ऊँट का सिर शर्म से झुक गया। वह चुपचाप वहाँ से खिसक गया।

शिक्षा -दूसरों की कमियाँ ढूँढ़ने के पहले अपनी कमियों पर नजर ड़ालिए।

हल करो हीरो बनो

1. कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है।
(क) सांप (ख) केंचुआ
(ग) बन्दर (घ) मनुष्य
2. निम्नलिखित में से किसकी तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है।
(क)दृश्यमान किरणें (ख) गामा किरणें
(ग) अवरक्त किरणें (घ) एक्स किरणें
3. 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में दांडी मार्च किस ब्रिटिश नीति के विरोध में एक महत्वपूर्ण विरोध प्रदर्शन था।
(क) नील की खेती (ख) नमक कर
(ग) भूमि राजस्व (घ) वस्त्र व्यापार नियम
4. निम्नलिखित में से कौन सा सदिग राशि का एक उदाहरण है।
(क) लंबाई (ख) गति
(ग) कार्य (घ) विस्थापन
5. जब बस अचानक शुरु होती है तो यात्री पीछे की ओर धकेले जाने का अनुभव करता है। यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है।
(क) न्यूटन का पहला नियम (ख) न्यूटन का दूसरा नियम (ग) न्यूटन का तीसरा नियम (घ) इनमें से कोई भी नियम नहीं

(उत्तर इसी अंक में)

भार लो मुस्की

पत्नी: अगर मैं खो गई तो आप क्या करेंगे?
पति: मैं अखबार में विज्ञापन दूँगा।
पत्नी: आप कितने अच्छे हैं, क्या लिखेंगे?
पति: जिसको मिले, उसी की!

▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶

मरीज: डॉक्टर साहब, जब मैं सोता हूं, तो सपने में फुटबॉल खेलता हूं।
डॉक्टर: तो इसमें क्या परेशानी है?
मरीज: सुबह जब उठता हूं, तो मेरी कमर टूट रही होती है!

▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶

भगवान: क्या चाहिए तुझे?
काका : एक नौकरी,
पैसो से भरा कमरा, सुकून की नींद और गर्मी से छुटकारा
भगवान : तथास्तु !
आज काका एटीएम में गार्ड है !

▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶

एक शादी शुदा आदमी ने अपनी कविता में कहा है....
मांग भरने कि सज़ा कुछ इस कदर पा रहा हूँ की मांग पूरी करते करते मांग के खा रहा हूँ...

▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶

टीचर- एक तरफ पैसा और दूसरी तरफ अक्कल, क्या चुनोगे?
विद्यार्थी- पैसा
टीचर- गलत, मै अक्कल चुनती.
विद्यार्थी- आप सही कह रही हो मैडम, जिसके पास जिस चीज की कमी होती है वो वही चुनता है।

▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶

आज कल के मा-बाप सुबह स्कूल बस में बच्चे को बैठा के ऐसे बाय-बाय करते हैं, जैसे पढ़ने नहीं, विदेश यात्रा पर भेज रहें हो।
और एक हम थे, जो रोज़ लात खा के स्कूल जाते थे।

▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶

माँ : बेटा क्या कर रहे हो
बेटा : पढ रहा हु माँ
माँ : शाबास! क्या पढ रहे हो
बेटा : आपकी होने वाली बहु के एसएमएस, दे थप्पड़ दे थप्पड़।

▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶

शादी के बाद पहली बार बहू रेसिपी बुक देखकर खाना बना रही थी...
सास (फ्रिज खोलती है): अरे बहू ये मंदिर का घंटा फ्रिज में क्यों रखा है?
बहू- मम्मी जी बुक में लिखा है कि सब चीजों को मिलाकर एक घंटा फ्रिज में रखें।
सास बेहोश...

▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶

पत्नी : सुनो जी
सोमवार खरीदारी, मंगल को होटल प्रोग्राम, बुध को लॉग ड्राइव पर, गुरुवार चायनीज रेस्टॉरेन्ट, शुक्रवार मूवी देखेंगे, शनीवार को पिकनिक कितना मजा आएगा ना
पति: जरूर और रविवार को मंदिर जाएँगे।
पत्नी : '' क्यों ?? ''
पति : भीख माँगने।

▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶

पत्नी- तुम शराब में बहुत पैसे बर्बाद करते हो अब बंद करो
पति- और तुम ब्यूटी पार्लर में 5000 का कबाड़ा करके आती हो उसका क्या?
पत्नी- वो तो मैं तुम्हें सुंदर लगूं इसलिए पति-पगली मैं तो इसलिए पीता हूं कि तू मुझे सुंदर लगे।

▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶

माथापच्ची–22

3	4							7
		7			9			
	8	1		3	4			
2				6		1		5
1	3						7	6
8		4		1				9
			1	4		5	6	
			8			2		
4							3	1

नियम : प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक अंक भरे जाने आवश्यक है, इनका क्रमवार होना आवश्यक नहीं है। आड़ी एवं खड़ी पंक्ति में एवं 3X3 के वर्ग में अंक की पुनरावृत्ति न हो, पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते।

उत्तर अगले अंक में

माथापच्ची 21 का हल

3	9	2	6	4	1	7	5	8
8	5	1	9	2	7	3	4	6
7	4	6	5	3	8	2	9	1
9	3	4	2	8	6	1	7	5
5	2	7	4	1	9	6	8	3
6	1	8	7	5	3	4	2	9
2	6	5	3	9	4	8	1	7
1	7	9	8	6	2	5	3	4
4	8	3	1	7	5	9	6	2

रोमांच की चाह में सातवीं कक्षा के छात्र ने साइकिल से 70 किमी का सफ़र किया!

समंदर की लहरों ने किशोर को अपनी ओर खींचा

निज संवाददाता : एडवेंचर के जोश में सातवीं कक्षा का एक छात्र साइकिल से 70 किमी का सफर तय करके दीघा पहुंचा। दरअसल इस किशोर को 'अनजान का टच' करने का जुनून था। भूपतिनगर का किशोर सुजन जाना इस रोमांच के टच को इग्नोर नहीं कर सका। किशोर अपनी हमेशा की साथी साइकिल के साथ 70 किमी का सफर तय करके दीघा पहुंचा। सुजन जाना पूर्व मेदिनीपुर के भूपतिनगर का रहने वाला है। उसका घर मधकाली इलाके में है। वह सातवीं क्लास का छात्र है। समंदर की लहरें, पूर्णिमा की रात में बहते हुए चरागाह और कोहरे वाली रात में पड़ती रोशनी ने उसे अपनी ओर खींचा। काम के प्रेशर की वजह से उसके माता-पिता उसे समंदर किनारे के शहर दीघा नहीं ले जा सके। ज़ाहिर है, अगर वह घर पर पूछता तो माता-पिता उसे अकेले जाने नहीं देते, यह किशोर जानता था। और तो और, उसके पास दीघा जाने के लिए पैसे कहां से आएंगे? इसलिए बिना किसी को बताए, वह अपनी साइकिल के साथ दीघा पार कर गया। अपने बेटे को न पाकर परिवार वाले पागल हो गए। माता-पिता घबराकर उसकी तलाश करने लगे। उन्होंने गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज कराई। इस बीच, गुरुवार रात को सुजन को दीघा के विश्व बांग्ला वन पार्क के सामने घूमते देखा गया। लड़के को बिना किसी मकसद के घूमते देख सिविल डिफेंस के आपदा प्रबंधन समूह के ग्रीन गार्ड शोभन जाना को शक हुआ। जब उन्होंने उससे पूछताछ की, तो लड़के ने उन्हें बताया कि वह किसी को बताए बिना घर से साइकिल से अकेले दीघा आया था। शोभन ने कहा- भूपतिनगर थाने के मधकाली इलाके के रहने वाले सुरजीत जाना का बेटा सुजीत बिना किसी को बताए दीघा आया था। लड़के को देखकर उन्हें शक हुआ। जब उससे पूछताछ की गई, तो उसने कहा कि वह घर से अकेला आया है। सुजन को बचाकर पुलिस के पास रखा गया। परिवार को सूचित किया गया। उसे उसी रात उसके परिवार को सौंप दिया गया।

एलपीजी के संकट से गुजर रहा खड़गपुर आईआईटी

संस्थान के 15 हजार छात्रों के लिए हर दिन पड़ती है सौ से ज्यादा गैस सिलेंडर की ज़रूरत!

निज संवाददाता : खड़गपुर आईआईटी संस्थान एलपीजी संकट से गुजर रहा है। यहां के अधिकारी एलपीजी की कमी का सामना कर रहे हैं। वे अब 15 हज़ार आवासीय छात्र को खाना देने के लिए लकड़ी के ईंधन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने पश्चिम मेदिनीपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से इस नई स्थिति में दखल देने की अपील की है। खड़गपुर आईआईटी के 20 रेजिडेंशियल हॉल में करीब 15 हज़ार छात्र हैं। उनके लिए दिन में तीन बार का खाना कैंटीन में बनता है। अधिकारियों ने बताया कि खाना पकाने के लिए हर दिन औसत 104 गैस सिलेंडर की ज़रूरत होती है। नई स्थिति में, लकड़ी के चूल्हों पर खाना बनाना शुरू हो गया है। लेकिन यह कब तक चलेगा। इसलिए आईआईटी अधिकारियों ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पत्र भेजकर समस्या का हल मांगा है। खड़गपुर आईआईटी कैंपस के आज़ाद हॉल के मैनेजर अविजित रॉय ने कहा-दो दिनों से कुकिंग गैस की दिक्कत है। इस वजह से, हमें अपने हॉल में रहने वाले करीब 800 छात्रों के लिए लकड़ी के चूल्हे में दिन में दो बार खाना बनाना पड़ रहा है। हालांकि, कोई भी डिश बहुत ज़्यादा फ्राइड नहीं बन पा रही है। छात्रों को लंच और डिनर के अलावा रेगुलर टिफिन मिले, इसका इंतज़ाम किया जा रहा है। हालांकि, तब भी मेन्यू में कभी-कभी बदलाव करना पड़ता है। आईआईटी खड़गपुर की तरफ से पश्चिम मेदिनीपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बिजिन कृष्णा को एक लेटर भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि कैंपस के 20 हॉल के लिए हर दिन 104 सिलेंडर की ज़रूरत है।

यहां करीब 15,000 छात्र हैं। उनके लिए हॉल में दिन में दो बार खाना बनाने का इंतज़ाम किया गया है। यहां दो तरह के मील हैं-नॉन-वेजिटेरियन और नॉन-वेजिटेरियन- टिफिन। लेकिन अब शैक्षिक संस्था गैस की कमी से जूझ रहा है। आईआईटी कैंपस के गैस गोदाम में और सिलेंडर नहीं हैं। कैंपस के बीसी रॉय हॉस्पिटल के लिए चार सिलेंडर स्टॉक में रखे गए हैं। ऐसे में, सिलेंडर की कमी को तुरंत पूरा करने का इंतज़ाम करने को कहा गया है। नहीं तो, हमें 15,000 छात्रों को रोज़ाना खाना देने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।

पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन 23 मार्च से करेगा शिक्षक भर्ती इंटरव्यू

निज संवाददाता : स्कूल सर्विस कमीशन (एसएससी) 23 मार्च से 23 मई के बीच सेकेंडरी टीचर की नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के डॉक्यूमेंट्स वेरिफ़ाई करेगा और इंटरव्यू और लेक्चर डेमोंस्ट्रेशन (साक्षात्कार और व्याख्यान प्रदर्शन) करेगा। हायर सेकेंडरी शिक्षकों के लिए काउंसलिंग 24 मार्च से शुरू होगी और 8 मई तक चलेगी। कमीशन के एक अधिकारी ने कहा कि शेड्यूल इसलिए तय किया गया है ताकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय 31 अगस्त की डेडलाइन तक भर्तियां पूरी हो सकें। एसएससी पहले ही 31 दिसंबर, 2025 की पहली डेडलाइन चूक चुका है। कमीशन के चेयरमैन के साइन किए हुए एक नोटिस में कहा गया है-कमीशन, टीचिंग पोस्ट, क्लास लेवल 9-10 और 11-12 दोनों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय समय सीमा (भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए) का पालन करने की पूरी कोशिश में, टीचिंग सेक्टर के लिए बाकी काम का टेंटेटिव शेड्यूल जारी करता है। डिटेल्स कमीशन की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई हैं। सहायक शिक्षक के तौर पर अपॉइंट होने के लिए रिकमेंडेशन लेटर जारी करने से पहले, किसी रीजन में मौजूद वैकेंसी के बारे में एम्पैनल्ड कैंडिडेट को बताने के लिए काउंसलिंग होती है। एसएससी ने 14 सितंबर को क्लास 12 का सिलेक्शन टेस्ट किया था, जबकि क्लास 10 का एसएलएसटी 7 सितंबर को हुआ था।डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान, एसएससी कैंडिडेट्स के ऑनलाइन एप्लीकेशन में जमा किए गए एकेडमिक स्कोर को क्रॉस-चेक करेगा, जो उनके अंडरग्रेजुएट फाइनल मार्क्स पर आधारित थे। एसएससी के एक अधिकारी ने कहा- एकेडमिक स्कोर कैलकुलेशन में गलतियों की वजह से 2016 में हुए पिछले सिलेक्शन प्रोसेस को कैंसल कर दिया गया था। हम इसे दोहराना नहीं चाहते हैं। लेक्चर डेमोंस्ट्रेशन स्क्रीनिंग के हिस्सों में से एक है।कमीशन ने हायर सेकेंडरी लेवल पर टीचरों की भर्ती के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू खत्म कर दिए हैं। अब यह 12,514 शिक्षकों की भर्ती में व्यस्त है।

पाइप और श्रमशक्ति की कमी से कोलकाता में 'अमादेर पाड़ा अमादेर समाधान' प्रोजेक्ट्स में हो रहीं देरी

निज संवाददाता : अंडरग्राउंड ड्रेनेज पाइप और सड़क मरम्मत के लिए कच्चे माल की कमी की वजह से 'अमादेर पाड़ा अमादेर समाधान स्कीम' के तहत प्रोजेक्ट्स को लागू करने में देरी हो रही है।एक पार्षद के सवाल का जवाब देते हुए, कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने कहा कि ड्रेनेज पाइप की अभी भी कमी है, लेकिन सड़क मरम्मत के सामान की कमी दूर कर ली गई है। हकीम ने कहा कि स्कीम के तहत सिर्फ़ 40 फीसदी प्रोजेक्ट्स ही पूरे हुए हैं। जब जुलाई 2025 में इस स्कीम की घोषणा की गई थी, तो कहा गया था कि सभी प्रोजेक्ट्स 15 जनवरी तक पूरे हो जाएंगे। हकीम ने कहा-मैंने कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (केएमसी) और कोलकाता मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (केएमडीए) से दूसरे ऑप्शन देखने को कहा है।राज्य के शहरी विकास मंत्री होने के नाते, हकीम केएमडीए के चेयरमैन भी हैं, जो कलकत्ता मेट्रोपॉलिटन एरिया में इस स्कीम के तहत प्रोजेक्ट्स को पूरा कर रहा है। वार्ड 48 के पार्षद विश्वरूप डे ने केएमसी के मासिक अधिवेशन में देरी की बात उठाई। उन्होंने यह भी कहा कि मैनपावर की कमी है। केएमसी अधिकारियों ने माना कि मैनपावर की कमी से प्रोजेक्ट्स में देरी हो रही है। मालूम हो कि 'अमादेर पाड़ा अमादेर समाधान स्कीम' के लिए ₹364.93 करोड़ दिए गए थे।

ढाई साल बंद रहने के बाद फिर से खुलेगा सिक्किम का मशहूर पर्यटन स्थल

एशिया की सबसे ऊंची झीलों में से एक है लाचेन और गुरुडोंगमार

निज संवाददाता : सिक्किम का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल लाचेन, लगभग ढाई साल के अंतराल के बाद आखिरकार पर्यटकों के लिए फिर से खुल गया है। अक्टूबर 2023 में ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (हिमनद झील के फटने से बाढ़) की वजह से हिल स्टेशन से रोड संपर्क टूटने के बाद, लाचेन और गुरुडोंगमार झील, जो एशिया की सबसे ऊंची झीलों में से एक है और 17,100 फीट की ऊंचाई पर है, वहां टूरिस्ट का आना-जाना बंद हो गया था। इस वर्ष 26 फरवरी को, राज्य सरकार ने बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन और भारतीय सेना के साथ मिलकर, मंगन जिले में चुंगथांग और लाचेन के बीच कनेक्टिविटी बहाल की। इसके लिए, ताराम चू, जो एक अशांत पहाड़ी नदी है, पर बेली सस्पेंशन ब्रिज खोला गया।

क्यों हो रही है योगी सरकार की छवि धूमिल करने की राजनीति

यूपी चुनाव के मद्देनजर अखिलेश यादव की रणनीति का हिस्सा?

निज संवाददाता : समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव इन दिनों मोदी-योगी और बीजेपी के तमाम नेताओं के खिलाफ अपनी तीखी भाषा और तंज भरी शैली के चलते राजनीतिक हलकों में छाए हुए हैं। वे लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते रहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कांग्रेस के राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हैं। अखिलेश, सीएम योगी की छवि को धूमिल करने के लिए हर मौके को हथियार बनाते हैं। योगी की वेशभूषा पर सवाल उठाते हैं तो उनकी क्षमता पर भी चोट करते हैं। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की तारीफ देश-दुनिया कर रही हो, अखिलेश उसी पर तंज कसते हैं। भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, निवेश प्रयासों का मजाक उड़ाते हैं। यहां तक कि योगी के विदेश दौरों को भी निशाने पर लेते हैं। वे उपमुख्यमंत्रियों केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के बीच कलह की अफवाहें फैलाते हैं। उन्हें सौ विधायक लाने और मुख्यमंत्री बनने का प्रस्ताव देते रहते हैं। अब तो यह भी कह रहे हैं कि 2027 का विधानसभा चुनाव नहीं होगा, बल्कि 2029 का लोकसभा चुनाव ही होगा। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के बहाने भी योगी पर प्रहार कर रहे हैं। ये सारी बातें अखिलेश की रणनीति का हिस्सा लगती हैं, जो योगी सरकार को कमजोर दिखाने पर तुली हुई हैं। खैर, राजनीति में बयानबाजी का यह खेल पुराना है, लेकिन अखिलेश इसे एक कला बना चुके हैं। वे हर सार्वजनिक मंच पर योगी को निशाना बनाते हैं। योगी जब भी कोई नया कदम उठाते हैं, अखिलेश तुरंत उस पर सवाल खड़े कर देते हैं। मसलन, योगी के विदेश भ्रमणों को वे व्यर्थ बताते हैं। कहते हैं कि ये दौरे केवल दिखावा हैं, असल में प्रदेश का विकास रुका हुआ है। निवेश सम्मेलनों का भी वे मजाक उड़ाते हैं। दावा करते हैं कि ये सब आंकड़े काल्पनिक हैं, जमीन पर कुछ नहीं हो रहा। कानून व्यवस्था पर तो उनकी बोलचाल में सबसे ज्यादा तीखापन आता है। योगी सरकार जब अपराध पर सख्ती की बात करती है, अखिलेश पुराने आंकड़े निकालकर हमला बोलते हैं। कहते हैं कि अपराधी अभी भी खुले घूम रहे हैं, पुलिस की कार्रवाई केवल नाम की है। भ्रष्टाचार के आरोप तो वे रोजमर्रा की बात की तरह लगाते हैं। विभागों पर भ्रष्टाचार का ठप्पा लगाते हैं, अधिकारियों को निशाना बनाते हैं। योगी की वेशभूषा पर तंज कसना उनका पुराना शगल है। भगवा वस्त्रों को लेकर व्यंग्य करते हैं। कहते हैं कि यह आडंबर है, असली सेवा जमीन पर दिखानी चाहिए। इन तमाम हमलों से योगी की साफ-सुथरी छवि पर ग्रहण लगाने की कोशिश साफ झलकती है। अखिलेश की रणनीति में उपमुख्यमंत्रियों को शामिल करना नई चाल है।

वे केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के बीच दरार की कहानियां गढ़ते हैं। कहते हैं कि योगी के नेतृत्व में ये दोनों असहज हैं। उन्हें बार-बार ललकारते हैं सौ विधायक लाओ, मुख्यमंत्री बन जाओ। यह बयान भाजपा के अंदर कलह फैलाने का प्रयास है। अखिलेश जानते हैं कि भाजपा की एकजुटता ही उसकी ताकत है। इसलिए वे छोटे-छोटे बीज बोकर दरार पैदा करने की कोशिश करते हैं। मौर्य और पाठक को निशाना बनाना इसलिए आसान है

यह सारी रणनीति 2027 के चुनाव के लिए है। अखिलेश जानते हैं कि योगी मजबूत हैं, लेकिन कमजोरियां ढूंढनी हैं। कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी ये मुद्दे उठाकर वे वोटरों को लुभाते हैं। शंकराचार्य का मुद्दा धार्मिक वोट प्रभावित करेगा। उपमुख्यमंत्रियों पर हमला भाजपा को बांटेगा। चुनाव न होने का दावा भय पैदा करेगा। अखिलेश की तंज शैली उन्हें अलग बनाती है। वे भाषणों में कविताएं सुनाते हैं, मुहावरों का इस्तेमाल करते हैं। युवा उन्हें पसंद करते हैं। सोशल मीडिया पर उनके क्लिप्स ट्रेंड करते हैं। समाजवादी पार्टी को नई ऊर्जा मिल रही है। योगी सरकार को सतर्क रहना होगा।

क्योंकि वे पिछड़े वर्ग और अन्य समुदायों के प्रतिनिधि हैं। अखिलेश इनके माध्यम से समाजवादी समर्थकों को लुभाने का प्रयास करते हैं। योगी पर सीधा हमला न हो सके तो अप्रत्यक्ष रूप से सरकार को कमजोर दिखाते हैं। यह चाल चाणक्य नीति जैसी लगती है, जहां शत्रु को अंदर से तोड़ा जाता है। भाजपा कार्यकर्ता इन बयानों से भड़कते हैं, लेकिन अखिलेश को इससे सुर्खियां मिलती हैं। मीडिया इन बयानों को प्रमुखता से दिखाता है, जिससे अखिलेश का संदेश दूर-दूर तक फैलता है।

सबसे चौंकाने वाला बयान तो 2027 के विधानसभा चुनाव न होने का है। अखिलेश कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अब विधानसभा चुनाव नहीं होगा, 2029 का लोकसभा चुनाव ही मुख्य होगा। यह बयान केंद्र और राज्य की सत्ता पर सवाल उठाता है। विपक्षी नेता इसे लोकतंत्र पर हमला बताते हैं, लेकिन अखिलेश इसे हथियार बनाते हैं। वे कहते हैं कि भाजपा चुनाव से डर रही है, इसलिए इसे टालने की साजिश रच रही है। यह दावा आधारहीन लगता है, लेकिन अखिलेश के समर्थकों में उत्साह भर देता है। वे इसे योगी सरकार की नाकामी का प्रमाण बताते हैं। वास्तव में यह बयान भविष्य की राजनीति को प्रभावित करने का प्रयास है। 2027 का चुनाव भाजपा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि योगी की लोकप्रियता परखी जाएगी। अखिलेश पहले से ही प्रचार शुरू कर चुके हैं। समाजवादी कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के लिए यह बयान हवा में आग लगाने जैसा है। विपक्षी दल इसे दोहराते हैं, जिससे माहौल गरमाता जाता है। अखिलेश की यह शैली उन्हें युवा वोटरों का चहेता बनाती है। उनकी भाषा सरल, तीखी और याद रखने लायक होती है।

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का मुद्दा उठाकर अखिलेश ने धार्मिक भावनाओं को भी छुआ है। शंकराचार्य ने योगी सरकार पर आलोचना की, तो अखिलेश ने इसे पकड़ लिया। वे कहते हैं कि धार्मिक नेता भी योगी से नाराज हैं। यह बयान हिंदू वोट बैंक को भेदने की कोशिश है। योगी की हिंदुत्व छवि मजबूत है, लेकिन अखिलेश इसे कमजोर करने पर तुले हैं। शंकराचार्य के बहाने वे कहते हैं कि योगी धार्मिक मामलों में भेदभाव करते हैं। यह प्रहार सीधा सीने पर है। उत्तर प्रदेश में धर्म का महत्व बहुत है, इसलिए अखिलेश इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। वे हर धार्मिक आयोजन पर योगी को घेरते हैं। राम मंदिर निर्माण हो या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, इनका श्रेय योगी को देते हुए भी कमियां निकालते हैं। अखिलेश की यह रणनीति लंबे समय से चल रही है। मुलायम सिंह यादव के जमाने से समाजवादी पार्टी विपक्ष की भूमिका निभाती रही है। लेकिन अखिलेश ने इसमें आधुनिकता जोड़ी है। सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, छोटे वीडियो बनवाते हैं। उनके बयान वायरल होते हैं, लाखों लोग देखते हैं। दरअसल, योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता अखिलेश के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। योगी ने पांच साल में विकास के कई काम किए हैं। सड़कें बनीं, बिजली पहुंची, अपराध पर नियंत्रण हुआ। निवेश सम्मेलनों से अरबों के प्रस्ताव आए। लेकिन अखिलेश इन सबको नकारते हैं। वे कहते हैं कि ये सब कागजी हैं, किसानों की हालत खराब है। बेरोजगारी बढ़ रही है, युवा परेशान हैं। महंगाई पर भी तंज कसते हैं। योगी के बुलडोजर अभियान को अन्याय बताते हैं। कहते हैं कि निर्दोषों के घर तोड़े जा रहे हैं। यह मुद्दा पिछड़े इलाकों में गूंजता है। इन्हीं बयानों के सहारे अखिलेश समाजवादी पार्टी को पुनर्जनन देने के लिए संघर्षरत हैं। 2017 में हार के बाद 2022 में फिर हार मिली। अब 2027 की तैयारी में जुटे हैं। उनकी तंज शैली वोटरों को जोड़ती है। खासकर यादव और मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत करती है। वे योगी को चुनौती देते हैं बहस हो तो आओ। लेकिन बहस से बचते हैं।

अखिलेश की भाषा में व्यंग्य का पुट ऐसा है कि सुनने वाले हंसते भी हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। वे योगी को महंत कहकर चिढ़ाते हैं। कहते हैं कि महंत साधु हैं, राजनीति में क्या करेंगे। वेशभूषा पर तंज मारते हुए कहते हैं कि भगवा पहनकर विकास नहीं होता। केशव प्रसाद मौर्य को ललकारते हुए कहते हैं कि साहब, साहब कहना बंद करो, सत्ता संभालो। ब्रजेश पाठक को चेतावनी देते हैं कि योगी के डर से मत डरो। ये बयान भाजपा के अंदर खलबली मचा देते हैं। योगी शांत रहते हैं, लेकिन उनके समर्थक जवाब देते हैं। राजनीतिक बहस तेज हो जाती है। अखिलेश को इससे फायदा होता है। वे विपक्ष के चेहरा बन चुके हैं। अन्य दल उनके पीछे आते हैं।

यह सारी रणनीति 2027 के चुनाव के लिए है। अखिलेश जानते हैं कि योगी मजबूत हैं, लेकिन कमजोरियां ढूंढनी हैं। कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी ये मुद्दे उठाकर वे वोटरों को लुभाते हैं। शंकराचार्य का मुद्दा धार्मिक वोट प्रभावित करेगा। उपमुख्यमंत्रियों पर हमला भाजपा को बांटेगा। चुनाव न होने का दावा भय पैदा करेगा। अखिलेश की तंज शैली उन्हें अलग बनाती है। वे भाषणों में कविताएं सुनाते हैं, मुहावरों का इस्तेमाल करते हैं। युवा उन्हें पसंद करते हैं। सोशल मीडिया पर उनके क्लिप्स ट्रेंड करते हैं। समाजवादी पार्टी को नई ऊर्जा मिल रही है। योगी सरकार को सतर्क रहना होगा। अखिलेश के हमले तेज होंगे। राजनीति का यह युद्ध जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश की सियासत में रोमांच बना रहेगा। अखिलेश यादव सुर्खियों के सितारे बने रहेंगे।

बदल गया पश्चिम बंगाल का राजनीतिक नक्शा

♦ वाम-कांग्रेस हाशिए पर
♦ 2026 में ममता-बीजेपी का होगा सीधा मुकाबला

निज संवाददाता : पश्चिम बंगाल का राजनीतिक परिदृश्य 2016 के विधानसभा चुनावों से लेकर 2021 और 2026 के चुनावों की तैयारी तक काफी बदल गया है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के प्रभुत्व वाली राज्य की 294 सीटों वाली विधानसभा में वाम-कांग्रेस गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की बढ़ती लोकप्रियता और टीएमसी के सुदृढ़ीकरण के बीच उतार-चढ़ाव देखने को मिले हैं, जो क्षेत्रीय गतिशीलता, जनसांख्यिकी और मतदाता सूची में बदलाव से प्रभावित हैं। 2016 में टीएमसी ने 2011 की वाम-विरोधी लहर को और मजबूत करते हुए 211 सीटों के साथ भारी बहुमत हासिल किया। वाम मोर्चा-कांग्रेस गठबंधन को केवल 32 सीटें मिलीं (गठबंधन के हिसाब से सीपीएम को 26 और कांग्रेस को 0), जिनमें कोलकाता, मुर्शिदाबाद और घाटाल जैसे औद्योगिक क्षेत्रों की कुछ सीटें शामिल थीं। भारतीय जनता पार्टी को केवल 3 सीटें मिलीं, जो मुख्य रूप से दार्जिलिंग और शहरी बाहरी इलाकों में थीं, जो इसकी शुरुआती उपस्थिति का संकेत देती हैं। टीएमसी ने दक्षिण बंगाल (उदाहरण के लिए- दक्षिण 24 परगना में 31/31) और शहरी कोलकाता (11 में से अधिकांश

सीटें) में शानदार जीत हासिल की, जबकि मुर्शिदाबाद जैसे मुस्लिम बहुल जिलों और ग्रामीण हुगली में वामपंथियों की ताकत बनी रही। 2011 के परिसीमन के बाद 23 जिलों में 294 निर्वाचन क्षेत्रों को स्थिर किया गया, जिससे टीएमसी के ग्रामीण आधार को मजबूती मिली। 2021 के चुनावों ने एक बड़ा बदलाव ला दिया, जिसमें भाजपा ने हिंदुत्व-एनआरसी के मंच पर 77 सीटें जीतकर जबरदस्त बढ़त हासिल की। उसने जंगलमहल (पश्चिम मेदिनीपुर, झाड़ग्राम, पुरुलिया, बांकुड़ा: 30 सीटें) और उत्तर बंगाल (दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी) में भी बढ़त बनाई। संदेशखाली जैसे मुद्दों और कोविड प्रबंधन में हुई गड़बड़ियों को लेकर सत्ता विरोधी लहर के बावजूद टीएमसी ने वापसी करते हुए 213 सीटें जीतीं। टीएमसी ने अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों (मालदा, मुर्शिदाबाद, दो 24 परगना: बड़ी बढ़त) में दबदबा बनाए रखा और दक्षिण 24 परगना (31 सीटें), हावड़ा (16) और हुगली (18) में अपनी सीटें बरकरार रखीं। भाजपा ने सीमावर्ती और आदिवासी क्षेत्रों में जीत हासिल की, लेकिन मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में उसे हार का सामना करना पड़ा, जहां टीएमसी की कल्याणकारी योजनाओं ने उसे 30 प्रतिशत से अधिक वोट शेयर दिलाए। चुनाव मानचित्र में टीएमसी की जीत (212 सीटें) और बीजेपी के बरकरार/चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों के कारण दृश्य रूप से बदलाव आया है। मार्च 2026 तक, अप्रैल-मई में चुनाव होने वाले हैं, और 15वीं विधानसभा का कार्यकाल 7 मई को समाप्त हो रहा है।विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) के बाद मतदाता सूचियों से 63.66 लाख नाम (मतदाताओं के 10 प्रतिशत से अधिक) हटा दिए गए हैं, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों, मतुआ (नमशूद्र) क्षेत्र और अल्पसंख्यक जिलों की 125 से अधिक सीटों पर जनसांख्यिकी में बदलाव आया है। इसके प्रभावों में मतुआ और उत्तरी बंगाल के उन क्षेत्रों में बीजेपी की संभावित बढ़त शामिल है, जहां नाम हटाए गए हैं, और यह टीएमसी के अल्पसंख्यक गढ़ों जैसे मुर्शिदाबाद और मालदा को चुनौती दे सकता है, जहां नाम हटाए जाने से भारी नुकसान हुआ है। 2011 के बाद परिसीमन ने सीमाएं तय कर दीं, लेकिन 2026 के एसआईआर मतदाता सूची ने नरम पुनर्निर्धारण का काम किया, जिससे मतुआ (नागरिकता के बाद) में भाजपा को मजबूती मिली और टीएमसी के कल्याणकारी प्रभुत्व की परीक्षा हुई। आर्थिक संकट - बढ़ता घाटा (2022-23 में 49,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 2026-27 में 1,05,000 करोड़ रुपये का ऋण)-और अंतरिम बजट में किए गए तुष्टीकरण (उत्तरी बंगाल के विकास के बजाय मदरसा निधि का उपयोग) ने विभाजन को और गहरा कर दिया।

ममता ने राज्य में पांच समुदायों के लिए की डेवलपमेंट बोर्ड बनाने की घोषणा

निज संवाददाता : मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में पांच समुदायों के लिए कल्चरल और डेवलपमेंट बोर्ड बनाने का ऐलान किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार मुंडा, कोरा, डोम, कुंभकार और सद्गोप समुदायों के लिए जल्दी से पांच अलग-अलग बोर्ड बनाना चाहती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बोर्ड इन समुदायों की भाषा और परंपरा की रक्षा करेंगे, साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में सुधार का भी ध्यान रखेंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य में तृणमूल सरकार 2013 से समाज के सामाजिक-आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बोर्ड बना रही है। जिन पांच समुदायों के लिए ममता ने बोर्ड बनाने की बात की है, उनमें मुंडा और कोरा समुदाय के लोग शेड्यूल्ड ट्राइब्स (एसटी) हैं। कुंभकार और सद्गोप अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से हैं। और 'डोम' समुदाय के लोग शेड्यूल्ड कास्ट में आते हैं। इन पांच समुदायों में से, मुंडा, कोरा और डोम समुदाय मुख्य रूप से राज्य के पश्चिमी जिलों (बांकुड़ा, पुरुलिया, झाड़ग्राम, पश्चिम मेदिनीपुर के कुछ हिस्से) में रहते हैं। सद्गोप, कुंभकार, हालांकि, राज्य के लगभग सभी जिलों में फैले हुए हैं। कई लोगों का मानना है कि डेवलपमेंट बोर्ड का गठन समुदायों के विकास के साथ-साथ आने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया गया है। माना जा रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की 'बेइज्जती' करने के आरोप पर हाल ही में हुए विवाद से यह आंकड़ा और उलझ गया है। राज्य के पश्चिमी जिलों में बीजेपी ज़्यादा मज़बूत है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का इस इलाके में लगभग दबदबा था। हालांकि, 2021 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने कुछ ज़मीन वापस हासिल की। झाड़ग्राम की चारों सीटों पर तृणमूल कांग्रेस कब्जा हो गया। तीन साल बाद, 2024 के लोकसभा चुनाव में, राज्य में सत्ताधारी पार्टी ने बीजेपी से बांकुड़ा, झारग्राम और मेदिनीपुर लोकसभा सीटें छीन लीं। 2019 और 2024 में, बीजेपी ने पुरुलिया लोकसभा सीट जीती। लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने अपना वोट शेयर बढ़ा लिया। ऐसे में,तृणमूल कांग्रेस विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के पश्चिमी इलाके को बिना बंधन के रखना चाहती है। कुछ का दावा है कि उसने इसी आंकड़े को ध्यान में रखते हुए पांच समुदायों के लिए मुख्यमंत्री विकास बोर्ड बनाने की घोषणा की। इसके अलावा, राष्ट्रपति के अनादर विवाद ने भी राज्य में सत्ताधारी पार्टी को बेचैन कर दिया है। बीजेपी ने राष्ट्रपति की आदिवासी पहचान को सामने रखकर तृणमूल कांग्रेस को घेरने की रणनीति

अपनाई है। राजनीतिक जानकारों के एक वर्ग का मानना है कि राष्ट्रपति पर विवाद के कारण अनुसूचित जातियों के वोट फिर से बीजेपी की ओर जा सकते हैं। हालांकि वह खुले तौर पर ऐसी संभावना को स्वीकार नहीं करती है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस पश्चिमी इलाके में अपनी राजनीतिक जमीन को और मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा, उत्तर बंगाल के जिलों में भी इन समुदायों की मौजूदगी साफ़ दिखती है। वोटों के हिसाब से उत्तर बंगाल की ज़मीन अभी भी तृणमूल के लिए बहुत उपजाऊ नहीं है। वहां भी राज्य की सत्ताधारी पार्टी पद्मा की तरक्की को रोकना चाहती है। इसलिए, भले ही इसे विकास के मकसद से बनाया गया हो, लेकिन यह डेवलपमेंट बोर्ड विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति के असर से बच नहीं पा रहा है। इत्तेफ़ाक से, मुर्मू पिछले शनिवार को इंटरनेशनल ट्राइबल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए पश्चिम बंगाल आई थीं। उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी के बिधाननगर में जिस जगह उनका प्रोग्राम होना था, उसे बदल दिया गया।
राष्ट्रपति का प्रोग्राम सुरक्षा कारणों से बागडोगरा के पास गोंसाईपुर में रखा गया। खुद राष्ट्रपति ने इस जगह के बदलाव पर नाराज़गी जताई। बाद में वे बिधाननगर पहुंचे और वहां से उन्होंने राज्य प्रशासन और मुख्यमंत्री पर जमकर निशाना साधा। राष्ट्रपति मुर्मू ने यह भी सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री या उनके कैबिनेट का कोई सदस्य एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने क्यों नहीं गया। इस मामले पर भारी हंगामा हुआ। बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस पर जानबूझकर राष्ट्रपति की बेइज़्ज़ती करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के दूसरे केंद्रीय नेताओं और मंत्रियों ने इस पर अपनी बात रखी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मीटिंग में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने उन सभी हमलों का जवाब दिया।

कांशीराम की विरासत पर सभी दलों ने लगाया दांव

यूपी की राजनीति बदलने की होड़

2027 का विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन उसकी आहट अभी से सुनाई देने लगी है। सपा सत्ता में वापसी का सपना देख रही है, बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने की तैयारी में है और कांग्रेस खोए हुए जनाधार को फिर से हासिल करना चाहती है। ऐसे में कांशीराम की विरासत एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गई है। लेकिन अंतिम फैसला हमेशा मतदाता ही करता है।

निज संवाददाता : उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई प्रतीक ऐसे रहे हैं जिनकी विरासत समय-समय पर नई सियासी व्याख्या के साथ सामने आती है। बहुजन आंदोलन के प्रणेता कांशीराम भी ऐसे ही नेता हैं। 15 मार्च को उनकी जयंती हर साल बसपा मनाती रही है, लेकिन इस बार तस्वीर कुछ अलग है। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी तक, लगभग सभी दल कांशीराम की राजनीतिक विरासत को अपने तरीके से याद कर रहे हैं। लखनऊ से दिल्ली तक कार्यक्रमों की शृंखला बन रही है, बहुजन संवाद की बातें हो रही हैं और पीडीए दिवस जैसे नए राजनीतिक नारे सामने आ रहे हैं। यह सब महज संयोग नहीं है, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बदलते सामाजिक समीकरणों का संकेत भी है। दिलचस्प यह है कि कांशीराम की राजनीति का मूल आधार कांग्रेस विरोध से ही बना था। 1980 और 1990 के दशक में उन्होंने जिस बहुजन राजनीति की नींव रखी, उसने कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में लगभग हाशिए पर पहुंचा दिया था। लेकिन अब वही कांग्रेस उनकी जयंती को परिवर्तन दिवस के रूप में मना रही है। 13 मार्च को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होने वाले कार्यक्रम में राहुल गांधी की मौजूदगी और बहुजन संवाद की योजना इसी कोशिश का हिस्सा है। कांग्रेस का तर्क है कि कांशीराम को किसी एक पार्टी के नेता के रूप में सीमित करके नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि उन्हें सामाजिक न्याय की लड़ाई के बड़े प्रतीक के रूप में समझना चाहिए। राहुल गांधी पिछले कुछ समय से सामाजिक न्याय, जातीय जनगणना और हिस्सेदारी की राजनीति को जोर-शोर से उठा रहे हैं। कांशीराम के उस पुराने नारे जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी को कांग्रेस आज अपने राजनीतिक तर्क के रूप में सामने रख रही है।
समाजवादी पार्टी की रणनीति भी कम दिलचस्प नहीं है। अखिलेश यादव ने कांशीराम की जयंती को पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है।

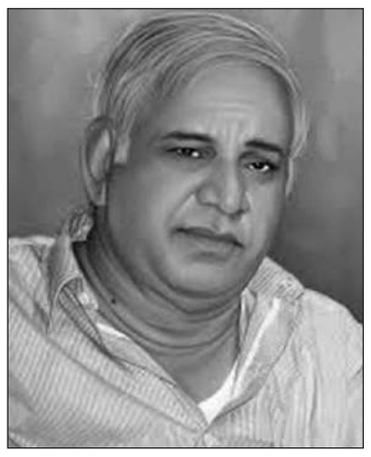

यह सिर्फ प्रतीकात्मक आयोजन नहीं है, बल्कि उस सामाजिक समीकरण को मजबूत करने की कोशिश है जो 2024 के लोकसभा चुनाव में आंशिक रूप से दिखाई दिया था। अखिलेश यादव को यह एहसास है कि सिर्फ यादव-मुस्लिम वोटों के सहारे बीजेपी को चुनौती देना मुश्किल है। इसलिए पीडीए का फार्मूला दरअसल उस बड़े सामाजिक गठबंधन की तलाश है जिसमें दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक एक साझा राजनीतिक मंच पर आएं। कांशीराम की जयंती को इस रणनीति से जोड़ना इसी सोच का हिस्सा है, क्योंकि बहुजन राजनीति की अवधारणा में यही सामाजिक वर्ग सबसे अहम रहे हैं। बीजेपी भी इस पूरी बहस से अलग नहीं है। पार्टी ने दलित महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि मनाने के लिए एक कैलेंडर तैयार किया है, जिसमें कांशीराम का नाम भी शामिल है। योगी सरकार के मंत्री असीम अरुण के नेतृत्व में दलित समाज से संवाद बढ़ाने की कोशिशें की जा रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में बीजेपी ने दलित समुदाय के बीच अपनी पैठ मजबूत करने के लिए कई प्रतीकात्मक और सामाजिक कार्यक्रम किए हैं। संत रविदास से लेकर बाबा साहेब आंबेडकर तक, दलित प्रतीकों को पार्टी अपने राजनीतिक विमर्श में शामिल कर चुकी है। ऐसे में कांशीराम का नाम भी इस सूची में जुड़ना स्वाभाविक माना जा रहा है। बीजेपी की रणनीति साफ है दलित समाज को यह संदेश देना कि उसकी राजनीति सिर्फ एक पार्टी की बपौती नहीं है। दरअसल, कांशीराम की विरासत को लेकर अचानक बढ़ी यह दिलचस्पी उत्तर प्रदेश की बदलती राजनीति से जुड़ी है। राज्य में दलित मतदाता लगभग 21 प्रतिशत हैं और अगर अतिपिछड़े वर्ग को जोड़ दिया जाए तो यह संख्या 50 प्रतिशत के करीब पहुंच जाती है। कांशीराम ने इन्हीं वर्गों को राजनीतिक ताकत के रूप में संगठित करने का काम किया था। बसपा के उदय के साथ दलित राजनीति को पहली बार ऐसा मंच मिला जिसने सत्ता तक पहुंचने का रास्ता बनाया। मायावती चार बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनीं और बहुजन राजनीति का एक नया अध्याय लिखा गया।
लेकिन पिछले कुछ चुनावों में बसपा का जनाधार लगातार कमजोर होता गया है। 2022 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन बेहद सीमित रहा। यही वह राजनीतिक खालीपन है जिसे भरने के लिए दूसरी पार्टियां कोशिश कर रही हैं। सपा को लगता है कि दलित मतदाता अब नए विकल्प की तलाश में हैं और पीडीए फार्मूले के जरिए उन्हें अपने साथ जोड़ा जा सकता है। कांग्रेस भी इसी संभावना को देख रही है और सामाजिक न्याय की नई बहस के जरिए दलित-ओबीसी वर्गों से संवाद बढ़ाना चाहती है। बीजेपी के सामने चुनौती थोड़ी अलग है। पार्टी ने 2014 के बाद से दलित वोटों में उल्लेखनीय बढ़त हासिल की थी, लेकिन 2024 के चुनाव में कई जगहों पर इस समर्थन में हल्की दरार दिखी। इसलिए बीजेपी भी सामाजिक इंजीनियरिंग के जरिए दलित और अतिपिछड़े वर्गों को अपने साथ बनाए रखने की रणनीति पर काम कर रही है। कांशीराम जैसे प्रतीकों को याद करना उसी व्यापक रणनीति का हिस्सा है।
असल सवाल यह है कि क्या कांशीराम की विरासत को सिर्फ राजनीतिक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करना ही काफी होगा? कांशीराम ने जिस बहुजन राजनीति की कल्पना की थी, उसका मूल उद्देश्य सत्ता में भागीदारी और सामाजिक सम्मान था। उन्होंने दलितों और वंचित वर्गों को यह एहसास कराया कि लोकतंत्र में संख्या भी ताकत होती है। उनकी राजनीति सिर्फ चुनाव जीतने की रणनीति नहीं थी, बल्कि सामाजिक चेतना का आंदोलन भी थी।
आज जब अलग-अलग पार्टियां उनकी जयंती मनाने की होड़ में हैं, तब यह भी देखना होगा कि उनकी मूल सोच को कितनी गंभीरता से अपनाया जाता है। क्या यह सिर्फ वोटों की गणित है या सामाजिक न्याय की वास्तविक चिंता भी है? यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रतीकों का इस्तेमाल नया नहीं है। अक्सर नेता और दल किसी बड़े सामाजिक नायक की विरासत को अपने पक्ष में पेश करते रहे हैं। 2027 का विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन उसकी आहट अभी से सुनाई देने लगी है। सपा सत्ता में वापसी का सपना देख रही है, बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने की तैयारी में है और कांग्रेस खोए हुए जनाधार को फिर से हासिल करना चाहती है। ऐसे में कांशीराम की विरासत एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गई है। लेकिन अंतिम फैसला हमेशा मतदाता ही करता है। यह वही मतदाता है जिसे कांशीराम ने कभी कहा था कि सत्ता की चाबी उसके हाथ में है। अब देखना यह है कि 2027 की लड़ाई में यह चाबी किसके ताले को खोलती है और किसकी राजनीति को नया रास्ता दिखाती है।

आजम का समय खराब तो अखिलेश का नये चेहरे पर दांव

यूपी की सियासत

संजय सक्सेना

उत्तर प्रदेश की सियासत में मुस्लिम मतदाता सदैव निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं। करीब 125 सीटों पर इनका असर सीधे नतीजों को प्रभावित करता है, खासकर पश्चिमी इलाके में जहां मुस्लिम आबादी चालीस फीसद तक पहुंच जाती है। भाजपा को छोड़ अन्य सभी दल इन मतों को हथियाने के लिए होड़ लगाए रहते हैं और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव इस दौड़ में सबसे आगे दिखते हैं। जेल में बंद आजम खान से लेकर बसपा और कांग्रेस छोड़ हाल ही में पार्टी में आए नसीमुद्दीन सिद्दीकी तक पर वे दांव लगा रहे हैं, ताकि यूपी में मुस्लिम वोटों के एक और सौदागर ओवैसी की बढ़ती चुनौती का मुकाबला हो सके। आज हालात यह है कि जेल में बंद आजम खान की कमी सपा के लिए गहरी चोट साबित हो रही है, क्योंकि रामपुर से सहारनपुर तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उन 60 से अधिक सीटों पर उनका जादू बरकरार है जहां मुस्लिम मतदाता जीत-हार तय करते हैं। जेल की चारदीवारी में बंद होते हुए भी उनके समर्थक बाहर चिल्ला रहे हैं, पश्चिमी इलाके के छह जिलों में मुस्लिम आबादी पैंतालीस फीसद से ऊपर होने के कारण वहां सपा का वोट बैंक डगमगाने लगा है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी इस कमी को कितना भर पाएंगे, यह सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि बसपा से होते हुए कांग्रेस तक अपनी यात्रा में उन्होंने बुंदेलखंड के दर्जन भर जिलों में मुस्लिम मतों को संगठित करने का लोहा मनवा लिया है। हाल ही में पंद्रह फरवरी को सपा में शामिल होने के बाद वे बुंदेलखंड की उन पचास सीटों पर फोकस कर रहे हैं जहां मुस्लिम आबादी तीस फीसद के आसपास है, और पूर्व में बसपा के प्रमुख मुस्लिम नेता के रूप में उन्होंने वहां सत्रह विधायकों को जुटाया था। नसीमुद्दीन की ताकत उनकी रणनीतिक चतुराई में है, जो आजम की जमीनी पकड़ से अलग लेकिन पूरक साबित हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आजम के खालीपन को वे पूरी तरह न भर सकें, क्योंकि वहां सहारनपुर से मुरादाबाद तक की इक्कीस मुस्लिम बहुल सीटों पर आजम का नाम ही वोट जुटाता रहा है। लेकिन बुंदेलखंड में उनकी पैठ गहरी है, जहां झांसी, बांदा, चित्रकूट जैसे जिलों की अट्ठारह सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक हैं और नसीमुद्दीन ने बसपा काल में इनमें से आधे पर असर डाला था। सपा को कुल मिलाकर एक सौ पचास सीटों पर फायदा हो सकता है, क्योंकि नसीमुद्दीन पूर्वांचल से बुंदेलखंड तक सौ से अधिक सीटों पर मुस्लिम युवाओं को लुभाने का दावा कर रहे हैं। ओवैसी की पार्टी हर ग्राम पंचायत में इकसठ सदस्यीय

समितियां गढ़ रही है, जो पश्चिमी इलाके की पचास सीटों पर सेंध लगा सकती है, लेकिन नसीमुद्दीन का अनुभव इस खतरे को कम कर सकता है।
सपा के अन्य मुस्लिम नेताओं द्वारा नसीमुद्दीन को स्वीकारना आसान नहीं होगा, क्योंकि पार्टी में पहले से इमरान मसूद जैसे सहारनपुर के दिग्गज हैं जिन्होंने पश्चिमी इलाके में दर्जन भर सीटों पर असर जमाया है। आशु मलिक जैसे नेता भी जिले के निकाय चुनावों में इमरान से टकरा चुके हैं, और सिसामऊ से इरफान सोलंकी तक सपा के छत्तीस मुस्लिम विधायकों में आंतरिक खींचतान पुरानी है। नसीमुद्दीन को बुंदेलखंड संभालने का मौका मिला तो इमरान सहारनपुर की आठ सीटों पर असहज हो सकते हैं, क्योंकि दोनों का वोट बैंक ओवरलैप करता है। लेकिन अखिलेश की चतुराई से यह संतुलन बन सकता है, क्योंकि पिछले चुनावों में सपा ने इक्यावन मुस्लिम बहुल सीटों पर मजबूत प्रदर्शन किया था और नसीमुद्दीन जैसे चेहरे से वह संख्या सत्तर तक पहुंच सकती है। आजम की कमी का असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उन छब्बीस जिलों में सबसे ज्यादा दिखेगा जहां मुस्लिम आबादी छब्बीस फीसद है, और सपा को वहां सत्तावन सीटें गंवाने का डर सता रहा है। नसीमुद्दीन इसकी भरपाई बुंदेलखंड से कर सकते हैं, जहां उन्होंने बसपा में अठारह नेताओं को संगठित किया था और अब सपा के सत्रह पूर्व विधायकों के साथ मिलकर चालीस सीटों पर दबदबा बना सकते हैं। ओवैसी का भूत सपा के सिर सवार है, क्योंकि उनकी पार्टी पंचायत स्तर पर बूथ मजबूत कर रही है और मुस्लिम युवाओं को छीनने की कोशिश में जुटी है, लेकिन नसीमुद्दीन का आना सपा को सांस लेने का मौका देगा। शिवपाल सिंह यादव की जेल मुलाकातें आजम का आशीर्वाद दिला सकती हैं, और अगर आजम ने हामी भरी तो नसीमुद्दीन को आगे बढ़ाया जाएगा। सपा की भाषा शैली अब बदल रही है, क्योंकि नसीमुद्दीन जैसे नेता मुस्लिम वोटों को जोड़ने के साथ जाट और पिछड़े समीकरण भी साधेंगे। उत्तर प्रदेश की कुल मुस्लिम आबादी पांच करोड़ के करीब पहुंच चुकी है, जो सवा सौ सीटों पर फैली हुई है। आजम के बिना पश्चिमी इलाके की उन तैंतीस सीटों पर खतरा बढ़ गया जहां मुस्लिम तीस फीसद से ज्यादा हैं, लेकिन नसीमुद्दीन बुंदेलखंड की उन सत्ताईस सीटों से भरपाई करेंगे जहां उनका पुराना नेटवर्क काम आएगा। पार्टी के अन्य मुस्लिम चेहरों जैसे नईम उल हसन या नफीस अहमद स्वीकार करेंगे या नहीं, यह आंतरिक कलह पर निर्भर है, लेकिन इमरान मसूद की असहजता पहले ही सतह पर आ चुकी है।
कुल मिलाकर नसीमुद्दीन आजम की कमी का आधा भर सकते हैं, क्योंकि पश्चिमी यूपी में आजम का जादू अनोखा है जो इक्कीस जिलों की सौ एक सीटों पर फैला है, जबकि नसीमुद्दीन बुंदेलखंड और पूर्वांचल की सौ सीटों पर मजबूत हैं। सपा के मुस्लिम नेताओं में कलह बरकरार रहेगी, क्योंकि सिकंदरपुर के जियाउर रिजवी से गोपालपुर के नफीस तक कई दावेदार हैं, लेकिन अखिलेश की रणनीति से संतुलन बनेगा। ओवैसी की आक्रामकता पश्चिमी इलाके में सेंध लगाएगी, लेकिन नसीमुद्दीन का सहारा सपा को मजबूत कर सकता है। योगी सरकार तुष्टीकरण पर हमला बोलेगी, पर अगर आजम का समर्थन मिला तो सपा बेदम नहीं पड़ेगी। इस जोड़ी की सफलता से सपा की कमर सीधी हो सकती है, वरना ओवैसी का डर हकीकत बन जाएगा।

सोनम वांगचुक को मिलेगी जेल से रिहाई

लद्दाख हिंसा पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला

निज संवाददाता : लद्दाख में हिंसा को लेकर गिरफ्तार किए गए सामाजिक कार्यकर्ता और इंजीनियर सोनम वांगचुक को मोदी सरकार ने रिहा करने का फैसला किया है। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत उनकी हिरासत को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। सोनम वांगचुक को लद्दाख में कुछ महीनों पहले हुई हिंसा के बाद गिरफ्तार किया गया था। सरकार का कहना है कि ये फैसला लद्दाख में शांति और स्थिरता का माहौल मजबूत करने और सभी पक्षों के साथ रचनात्मक संवाद को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है। सरकार के मुताबिक इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए और उचित विचार-विमर्श के बाद सोनम वांगचुक की हिरासत को तत्काल प्रभाव से रद्द करने का निर्णय लिया गया है। मालूम हो कि 24 सितंबर 2025 को लेह में हिंसा के चलते गंभीर कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा हो गई थी। सरकार के मुताबिक कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लेह के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के तहत सोनम वांगचुक को 26 सितंबर 2025 को एनएसए के प्रावधानों के अंतर्गत हिरासत में लिया गया था। सोनम वांगचुक हिरासत की अवधि का लगभग आधा समय जेल में बिता चुके हैं। केंद्र सरकार लद्दाख में विभिन्न हितधारकों और समाज के नेताओं के साथ सक्रिय रूप से संवाद कर रही है ताकि क्षेत्र के लोगों की चिंताओं का समाधान किया जा सके। हालांकि बंद और विरोध प्रदर्शनों का मौजूदा माहौल समाज के लिए बुरा साबित हुआ है। प्रदर्शनों के चलते छात्रों, नौकरी चाहने वालों, व्यवसायों, पर्यटन संचालकों और पर्यटकों सहित समुदाय के विभिन्न वर्गों को और लदाख की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान हुआ है। लद्दाख के इंजीनियर, शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक लंबे समय से शिक्षा और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय रहे हैं।

उन्होंने लद्दाख में शिक्षा सुधार और स्थानीय पर्यावरण संरक्षण को लेकर कई अभियान चलाए। आमिर खान की फिल्म थ्री इडियट्स में उनका कैरेक्टर फुनसुक वांगडू इन्हीं सोनम वांगचुक से प्रेरित था। पिछले कुछ समय से वे लद्दाख से जुड़े राजनीतिक और संवैधानिक मुद्दों को लेकर भी मुखर रहे हैं। खास तौर पर लद्दाख के लिए संवैधानिक सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय लोगों के अधिकारों को लेकर उन्होंने कई बार आंदोलन और प्रदर्शन किए थे।

पांच दिन से कम समय में साइकिल से 1500 किमी लंबे सहारा रेगिस्तान को पार किया

हावड़ा के तीन दोस्तों का साहसिक कारनामा

निज संवाददाता : हावड़ा के तीन दोस्तों ने एक ज़बरदस्त साहसिक काम किया। उन्होंने सिर्फ़ साढ़े चार दिनों में विशाल सहारा रेगिस्तान पार कर लिया। रास्ते में, वे गांव के होमस्टे में रुके और वहां के लोगों से मिले, अमिताभ बच्चन के बॉलीवुड गाने गाकर उनका मनोरंजन किया, और आखिर में दक्षिणी मिस्र में लेक नासिर पहुंचे। एवरेस्टर मलय मुखर्जी की लीडरशिप वाली टीम, जिसमें देवाशीष चक्रवर्ती और पार्थ प्रतिम हाज़रा शामिल थे, ने काहिरा की एक एजेंसी से साइकिल किराए पर ली। घर वापस आकर, उन्होंने 19 दिसंबर को मिस्र के मेडिटेरेनियन पोर्ट सिटी एलेक्जेंड्रिया से शुरू होने वाले नौ दिन के एक्सपीडिशन पर जाने से पहले कई महीनों तक अपनी स्टैमिना बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग ली। उन्होंने रेत के तूफ़ान, तेज़ हवाओं और बहुत ज़्यादा ठंड का सामना करते हुए साइकिल पर लगभग 1,500 किलोमीटर का सफ़र तय किया। चक्रवर्ती ने कहा-सहारा रेगिस्तान में साइकिल चलाना एक चैलेंज था जिसे हम लेना चाहते थे। कई किलोमीटर तक इंसानियत का कोई नामोनिशान नहीं होता था। हाईवे पर लगभग 150 किमी की रफ्तार से चलने वाले भारी ट्रक रेत उड़ाते थे, और ठंडे मौसम का मतलब था कि हमें शाम तक नाइट शेल्टर पहुंचना पड़ता था। रात में ज़्यादातर लोग गांव के होमस्टे में रुकते थे, जहां खाना बिना नमक के आमतौर पर उबला या भुना हुआ और पारंपरिक भारतीय करी के बिना परोसा जाता था। अनगिनत किलोमीटर तक पीली रेत पर साइकिल चलाते हुए, टीम को सबसे ज़्यादा जो बात खटकती थी, वह थी खेतों के बड़े-बड़े हिस्से, जो लगभग कहीं से भी नहीं दिखते थे, जहां टमाटर उगाए जाते हैं। पाइपलाइनों का जाल नील नदी से आने वाले पानी से ज़मीन को हाइड्रेट रखता था। चक्रवर्ती ने कहा-बातचीत करना मुश्किल था। कोई भी इंग्लिश नहीं बोलता था और न ही भाषा समझता था। लेकिन उनमें से ज़्यादातर भारत के बारे में जानने को उत्सुक थे, उन्होंने हमारे हाथों में तिरंगा देखा। कई लोगों के लिए भारत का मतलब अमिताभ बच्चन के गाने थे। गांव में, लोग उनके बॉलीवुड हिट गाने सुनने और उन पर डांस करने के लिए इकट्ठा होते थे और फिर तारीफ़ में हमें चाय और खाना देते थे।

एलेक्जेंड्रिया से काहिरा तक साइकिल से यह सफ़र दो दिन चला। साइकिल चलाने पर कई पाबंदियों का सामना करते हुए, तीनों ने शहर से बाहर निकलने और मिस्र की राजधानी से 500 किमी से ज़्यादा दूर नील घाटी के किनारे सोहाग पहुंचने के लिए एक कैब किराए पर ली, और फिर अपनी साइकिल पर निकल पड़े। अगले कुछ दिनों में, टीम ने अस्युत और लक्सर सहित कई खास जगहों को कवर किया। अस्युत अपनी पुरानी कब्रों के लिए जाना जाता है और मिस्र में कॉप्टिक ईसाइयों की सबसे ज़्यादा आबादी यहीं है। लक्सर ऊपरी मिस्र में नील नदी पर एक टूरिस्ट जगह है। चक्रवर्ती ने कहा-हमने साइकिल पर नील नदी के किनारे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वैली ऑफ़ द किंग्स और वैली ऑफ़ द क्वींस को पार किया और आखिर में दक्षिणी मिस्र में दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल झीलों में से एक, लेक नासर पहुंचे। उन्होंने इस अभियान का नाम 'साइकिल-ए-सहारा' रखा था।

अजब-गजब

नगरपालिका टैक्स से बचने के लिए शख्स ने निकाला अजब तरीका

पालतू कुत्ते को बनाया 'कचरा डिलीवरी बॉय'

निज संवाददाता : इटली के सिसिली द्वीप में एक व्यक्ति ने नगरपालिका के कूड़ा निस्तारण नियमों और टैक्स से बचने के लिए अपने ही पालतू कुत्ते का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यानी उसने कुत्ते को 'कचरा डिलीवरी बॉय' बना दिया। इस मामले ने स्थानीय प्रशासन से लेकर सोशल मीडिया तक सभी को हैरान कर दिया है। यह घटना कटानिया शहर के पास की है, जहां सीसीटीवी फुटेज में एक कुत्ता अपने दांतों में कचरे से भरा बड़ा प्लास्टिक बैग दबाए सड़क पर चलता दिखा। वह बड़ी सावधानी से सड़क किनारे रुकता है और बैग को वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाता है।शुरुआत में इसकी चतुराई देखकर सभी हैरान रह गए, लेकिन जांच में सामने आया कि यह कुत्ता रोजाना ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि उसके मालिक ने उसे ऐसा करने के लिए उसे प्रशिक्षित किया था। स्थानीय नगरपालिका ने जब यह वीडियो देखा, तो इस हरकत ने अधिकारियों को चौंका दिया। प्रशासन ने फुटेज जारी करते हुए कहा कि रचनात्मकता को कभी भी असभ्यता और नियमों के उल्लंघन का बहाना नहीं बनाया जा सकता। नगर पुलिस की पर्यावरण इकाई द्वारा रिकॉर्ड किए गए दो वीडियो में साफ दिखा कि कुत्ते को जानबूझकर कूड़ा फेंकने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। प्रशासन ने इसे दोहरा अपराध बताते हुए कहा कि इससे शहर की सफाई व्यवस्था को नुकसान पहुंचता है और साथ ही एक मासूम जानवर को गलत काम के लिए मजबूर किया जाता है। जांच में संबंधित व्यक्ति की पहचान कर ली गई और उस पर जुर्माना भी लगाया गया, हालांकि उसकी पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है। इस घटना के पीछे एक बड़ी समस्या भी उजागर होती है। इटली के दक्षिणी क्षेत्रों और आइलैंड्स में कचरा संग्रहण व्यवस्था लंबे समय से कमजोर रही है, जहां कभी-कभी केवल 57 प्रतिशत ही कचरा उठ पाता है। परिणामस्वरूप, कूड़े के ढेर कई दिनों तक डंपस्टर और कूड़ेदानों में पड़े रहते हैं।

गार्डिया दी फिनांज़ा की रिपोर्ट के अनुसार, इटली में हर वर्ष करीब दस हजार कचरे से जुड़े अपराध दर्ज किए जाते हैं, जिनमें अवैध डंपिंग, कूड़ा जलाना और जमीन में दबाना शामिल है। यहां अवैध तरीके से कचरा फेंकने पर 1,500 यूरो से लेकर 18,000 यूरो तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है और गंभीर मामलों में आपराधिक कार्रवाई भी हो सकती है।

अब आ गई पानी आधारित बैटरी

पर्यावरण अनुकूल इस खोज को चीन के वैज्ञानिकों ने दिया अंजाम

निज संवाददाता : चीन के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी बैटरी विकसित की है जो पूरी तरह से पानी पर आधारित है। इसे पारंपरिक लिथियम-आयन बैटरियों के सुरक्षित विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस बैटरी में इस्तेमाल किया गया इलेक्ट्रोलाइट इतना सुरक्षित है कि उसकी तुलना टोफू बनाने में इस्तेमाल होने वाले नमकीन घोल से की जा सकती है। इस पानी आधारित बैटरी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसे फेंकने पर यह पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करती, जबकि पारंपरिक बैटरियां खतरनाक कचरा मानी जाती हैं और उनका निस्तारण विशेष प्रक्रियाओं से करना पड़ता है। इसके अलावा, चूंकि इस बैटरी में ज्वलनशील पदार्थ नहीं हैं, इसलिए इसमें आग लगने का खतरा भी लगभग न के बराबर है। यही कारण है कि भविष्य में यह तकनीक इलेक्ट्रिक वाहनों और बड़े पावर ग्रिड स्टोरेज सिस्टम के लिए बेहद सुरक्षित विकल्प बन सकती है। 18 फरवरी को जर्नल नेचर कम्युनिकेशंस में प्रकाशित इस शोध में हांगकांग सिटी यूनिवर्सिटी और यानान यूनिवर्सिटी सहित कई अनुसंधान संस्थानों के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि उनकी विकसित की गई बैटरी 1,20,000 से अधिक चार्ज-डिस्चार्ज चक्र पूरे करने के बाद भी लगभग समान प्रदर्शन देती है। पारंपरिक लिथियम-आयन बैटरियों में जहां ज्वलनशील तरल पदार्थ का उपयोग होता है, वहीं आग लगने की घटनाओं से बचने के लिए इस नई बैटरी को खास तौर पर अधिक सुरक्षित बनाया गया है। कई बार उड़ानों में पावर बैंक के फटने या धुआं निकलने की घटनाएं सामने आई हैं, जिसका कारण इन्हीं ज्वलनशील इलेक्ट्रोलाइट का ओवरहीटिंग होता है। इस नई तकनीक में मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड जैसे प्राकृतिक रूप से मिट्टी में पाए जाने वाले रसायनों का इस्तेमाल किया गया है, जो पर्यावरण के लिए पूरी तरह हानिरहित हैं।

जापान के घने जंगलों में अनोखी चींटी की खोज

यह दुर्लभ प्रजाति परंपरागत नियमों को तोड़ते हुए केवल रानियों से बनी कॉलोनी का निर्माण करती है

निज संवाददाता : वैज्ञानिकों ने जापान के घने जंगलों में अनोखी चींटी की खोज की है। वैज्ञानिकों की इस ताजा खोज ने कीट जगत के स्थापित नियमों को पूरी तरह चुनौती दे दी है। चींटियों का समाज आमतौर पर बेहद अनुशासित होता है जहां रानी अंडे देती है, मजदूर भोजन जुटाते हैं और नर प्रजनन में भाग लेते हैं। लेकिन 'टेम्नोथोरैक्स किनोमुराई' नाम की यह दुर्लभ प्रजाति इन सभी परंपरागत नियमों को तोड़ते हुए केवल रानियों से बनी एक अनोखी कॉलोनी का निर्माण करती है, जिसमें न तो कोई नर होता है और न ही मेहनत करने वाले मजदूर। वैज्ञानिकों के मुताबिक, इस प्रजाति की सबसे बड़ी खासियत इसका प्रजनन तरीका है। यूनिवर्सिटी ऑफ रेगेन्सबर्ग के शोधकर्ताओं ने जब लैब में इन चींटियों का विश्लेषण किया, तो वे यह देखकर हैरान रह गए कि एक भी नर चींटी मौजूद नहीं थी। रिसर्च में सामने आया कि ये रानियां 'पार्थेनोजेनेसिस' नामक प्रक्रिया के जरिए प्रजनन करती हैं, जिसमें बिना नर के ही अंडों से संतति पैदा होती है। यानी ये रानियां अपनी ही तरह का क्लोन तैयार करती हैं। माइक्रोस्कोपिक जांच में यह भी पता चला कि इनके शरीर में मौजूद प्रजनन अंग कभी इस्तेमाल ही नहीं किए गए, जो इस तथ्य को और मजबूत करता है कि उनकी पूरी वंशावली बिना नरों के ही चल रही है। लेकिन इस प्रजाति का व्यवहार जितना अनोखा है, उतना ही हैरान करने वाला भी।चूंकि इनके पास मजदूर वर्ग नहीं होता, इसलिए ये अपनी जरूरतों के लिए अन्य प्रजाति 'टेम्नोथोरैक्स माकोरा' के घोंसलों पर निर्भर रहती हैं। युवा रानियां चोरी-छिपे माकोरा प्रजाति के घोंसलों में प्रवेश करती हैं और यहां पहुंचकर या तो अपनी जहरीली डंक से असली रानी को खत्म कर देती हैं, या वहां के मजदूरों को इस कदर भ्रमित कर देती हैं कि वे खुद अपनी रानी का कत्ल कर देते हैं। इसके बाद किनोमुराई की रानियां उस घोंसले पर कब्जा कर लेती हैं और वहीं के मजदूरों को अपना गुलाम बनाकर अपनी संतानों की देखभाल करवाती हैं। 'करंट बायोलॉजी' जर्नल में प्रकाशित इस शोध के अनुसार, यह प्रजाति सामाजिक परजीविता के चरम स्तर पर पहुंच चुकी है। जर्मनी के वैज्ञानिक जुर्गन हेंज के अनुसार, किनोमुराई का विकास कीट जगत में एक बिल्कुल नया अध्याय जोड़ता है। आम रानियों की संततियों में मजदूर और नर दोनों शामिल होते हैं, लेकिन इस प्रजाति की रानी की सभी संततियां रानी ही बनती हैं। इस वजह से इनके पास नए घोंसलों पर कब्जा करने और अपनी आबादी बढ़ाने के अधिक अवसर होते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह का विकासात्मक लचीलापन इन चींटियों को बेहद शक्तिशाली बनाता है।

महिला-स्वास्थ्य

बीमारी होने से पहले बेहतर है उसे रोकना

40वें पायदान से पहले महिलाओं को करवाने चाहिए कुछ अहम टेस्ट

निज संवाददाता : 40 की उम्र होते ही शरीर आपको कई तरह से बताता है। थकान होने लगती है। थोड़ी सी मेहनत करने पर भी पैरों और कमर में दर्द होने लगता है। जो काम पहले आसानी से हो जाते थे, वे भी मुश्किल होने लगते हैं। उम्र के साथ महिलाओं के शरीर में कई बदलाव आते हैं। बोन डेंसिटी कम हो जाती है, विटामिन की कमी हो जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है और हार्मोनल बैलेंस बिगड़ने लगता है। इसका असर शरीर पर पड़ता है। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है और आप लगातार स्ट्रेस में रहती हैं, तो आपको हार्ट की बीमारी का खतरा होता है। इसके अलावा, महिलाओं को सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर का भी खतरा होता है। खासकर, नींद की कमी, स्ट्रेस और अनकंट्रोल्ड लाइफस्टाइल से बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। डॉक्टरों का कहना है कि उम्र के साथ ऐसी समस्याओं या बीमारियों के खतरे से बचने के लिए पहले से सावधान रहना ज़रूरी है। पहले से कुछ टेस्ट ऐसी बीमारियों से बचने या बीमारियों को रोकने में मदद करते हैं। इलाहाबाद के एक हॉस्पिटल में कैंसर के डॉक्टर अर्पित बंसल बताते हैं कि 40 के करीब होने पर महिलाओं को किस तरह के टेस्ट करवाने चाहिए?

बोन डेंसिटी और विटामिन टेस्ट : 40 के करीब आते-आते बोन डेंसिटी कम होने लगती है। हड्डियां और मसल्स कमजोर हो जाती हैं। इस उम्र में विटामिन डी और बी12 की कमी बहुत आम है। डेक्सा स्कैन या बोन डेंसिटी टेस्ट करवाना ज़रूरी है। अगर बोन डेंसिटी कम हो रही है, तो शुरुआत में ही ज़रूरी दवाएं लेने से स्थिति और खराब नहीं होगी।

कैंसर का खतरा : महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर होने का खतरा ज़्यादा होता है। अगर बीमारी का पता शुरुआती स्टेज में चल जाए तो खतरे से बचा जा सकता है। इसके अलावा, अब कई तरह के टेस्ट से यह पता लगाया जा सकता है कि किसी को कैंसर का खतरा है या नहीं। जब आप 40 के करीब हों, तो डॉक्टर की सलाह पर पैप टेस्ट करवा सकते हैं। सर्वाइकल कैंसर की संभावना का पता लगाने के लिए एचपीवी स्क्रीनिंग की जाती है। एचपीवी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है। कुछ एचपीवी नुकसानदायक नहीं होते हैं। हालांकि, कुछ वायरस कैंसर का खतरा बढ़ाते हैं। यह टेस्ट कैंसर के खतरे की जांच करता है। यह टेस्ट पैप स्मीयर टेस्ट के दौरान भी किया जा सकता है।

ब्रेस्ट कैंसर टेस्ट : महिलाओं को 30 साल की उम्र के बाद खुद अपने ब्रेस्ट (स्तन) की जांच करने के लिए कहा जाता है ताकि पता चल सके कि कोई गांठ तो नहीं है। कोई भी महिला यह टेस्ट खुद कर सकती है। अगर आपको अपने ब्रेस्ट में कोई गांठ या ग्रोथ महसूस हो, तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर, आपका डॉक्टर मैमोग्राम करवाने की सलाह दे सकता है।

हार्ट टेस्ट : महिलाओं को भी हार्ट की बीमारी का खतरा रहता है। इसलिए, जल्द से जल्द हार्ट रेट टेस्ट करवाना ज़रूरी है। सबसे आम हार्ट टेस्ट ईसीजी है। इसके अलावा, अगर ज़रूरत हो, तो डॉक्टर इको समेत दूसरे टेस्ट भी कर सकते हैं।

वीओ2 मैक्स टेस्ट भी होता है। इससे यह टेस्ट होता है कि एक्सरसाइज़ के दौरान शरीर कितनी ऑक्सीजन सोख सकता है। हालांकि, यह आमतौर पर आम मेडिकल टेस्ट में शामिल नहीं होता है। ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर टेस्ट करवाने की सलाह दे सकते हैं।

दवा : कई बार शरीर में कई बदलाव होते हैं, लेकिन कोई लक्षण नहीं दिखते। जब वे लक्षण दिखते हैं, तो बीमारी भी फैलती है। इसलिए, पहले से टेस्ट करवाना और ज़रूरी दवाएं लेना ज़रूरी है। विटामिन बी12 और विटामिन डी की कमी से बचने के लिए, डॉक्टर की सलाह पर पहले से दवाएं शुरू की जा सकती हैं। बुढ़ापे तक स्वस्थ रहना तभी संभव होगा जब दिल और पेट स्वस्थ रहेंगे।

राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल उल्लंघन मामले में घमासान

♦ केंद्र ने दार्जिलिंग डीएम की मांगी डेप्युटेशन तो बंगाल सरकार ने कर दिया ट्रांसफर

निज संवाददाता : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रोटोकॉल उल्लंघन मामले में एक बार फिर केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार आमने सामने हैं। बीते शुक्रवार को केंद्र सरकार ने बंगाल की मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती से कहा कि वे दार्जिलिंग के डीएम मनीष मिश्रा और सिलीगुड़ी के पुलिस कमिश्नर सी. सुधाकर को सोमवार तक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली भेजें। इस पत्र के तुरंत बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने डीएम मनीष मिश्रा का गृह विभाग के स्पेशल सचिव के पद पर ट्रांसफर कर दिया। मनीष मिश्रा की जगह अब सुनील अग्रवाल को दार्जिलिंग का जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है। वह अभी तक उत्तर बंगाल विकास विभाग के स्पेशल सचिव थे। वहीं, पुलिस कमिश्नर सी. सुधाकर को लेकर अभी तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है। इससे पहले बंगाल सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को कथित प्रोटोकॉल उल्लंघन को लेकर विस्तृत स्पष्टीकरण दिया था, जिसके बाद केंद्र सरकार का यह लेटर अब बंगाल की मुख्य सचिव को आया है। बंगाल सरकार ने कहा कि राष्ट्रपति का विस्तृत कार्यक्रम केंद्र और राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा मंजूर किया गया था। इसमें उन अधिकारियों की सूची भी शामिल थी, जो उनका स्वागत करेंगे। डीएम मनीष मिश्रा, सीपी सी. सुधाकर और सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देब ने 7 मार्च को सिलीगुड़ी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया था। वहीं, गौतम देब ने शुक्रवार को इस मुद्दे पर टिप्पणी करने से परहेज किया। सिलीगुड़ी के विधायक और विधानसभा के मुख्य सचेतक शंकर घोष ने राष्ट्रपति मुर्मू से जुड़े इस घटनाक्रम की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का अपमान राष्ट्र का अपमान है। उन्होंने आगे कहा कि गृह मंत्रालय को इस मामले की जांच करने की जरूरत थी और उन्होंने ऐसा किया। 2015 बैच के आईएएस अधिकारी मनीष मिश्रा ने 27 अक्टूबर 2025 को दार्जिलिंग के डीएम का पदभार संभाला था। उन्होंने 2013 बैच की आईएएस अधिकारी प्रीति गोयल की जगह ली थी। प्रीति गोयल का तबादला करके उन्हें मालदा का डीएम बनाया गया था। दार्जिलिंग में अपनी नियुक्ति से पहले मनीष मिश्रा उत्तरी 24 परगना के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कार्यरत थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इंटरनेशनल आदिवासी एंड संताल काउंसिल के 9वें सम्मेलन में शामिल होने के लिए 7 मार्च को सिलीगुड़ी पहुंची थी। यह सम्मेलन शुरू में बिधाननगर, फांसीदेवा ब्लॉक के संतोषिनी स्कूल मैदान में आयोजित किया जाना था। इसे बाद में सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए बदल कर गोसाईंपुर, बागडोगरा कर दिया गया। बता दें कि बिधाननगर क्षेत्र सिलीगुड़ी के पास स्थित एक आदिवासी-बहुल इलाका है। कार्यक्रम स्थल में किए गए इस बदलाव पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सार्वजनिक रूप से अपनी नाराजगी जाहिर की थी। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद, वह बिधाननगर गईं और वहां भी उन्होंने कार्यक्रम स्थल में किए गए इस बदलाव को लेकर अपनी कड़ी असहमति व्यक्त की।

इस कथित प्रोटोकॉल उल्लंघन को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से 24 घंटे के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी। हालांकि रिपोर्ट जमा कर दी गई थी, लेकिन बताया जा रहा है कि केंद्र को यह रिपोर्ट संतोषजनक नहीं लगी। यह पहली बार नहीं है जब केंद्र और बंगाल के बीच इस तरह का टकराव हुआ है। 2021 के विधानसभा चुनावों से पहले दिसंबर 2020 में तत्कालीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की सुरक्षा व्यवस्था में चूक हुई थी। इस दौरान डायमंड हार्बर की ओर जा रहे उनके काफिले पर पत्थर फेंके गए थे। इस मामले में तीन आईपीएस अधिकारी, जो जेपी नड्डा की सुरक्षा की देखरेख के प्रभारी बनाए गए थे, उन्हें केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए चुना गया था। इसमें साउथ बंगाल के इंस्पेक्टर-जनरल राजीव मिश्रा, प्रेसिडेंसी रेंज के डिप्टी इंस्पेक्टर-जनरल प्रवीण कुमार त्रिपाठी और दक्षिण 24 परगना के सुपरिंटेंडेंट भोलानाथ पांडे शामिल थे। उन्हें 3 से 5 साल के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो में तैनात किया जाना था। उस समय भी राज्य सरकार ने इस कदम का विरोध किया था।

'मुझे टिकट दो, मैं जीता तो कृषि मंत्री बनूंगा'

हल लेकर बीजेपी दफ्तर पहुंचकर बांकुड़ा के किसान ने लगाई गुहार

निज संवाददाता : 28 साल से भगवा ब्रिगेड का समर्पित कार्यकर्ता। उसका खेतों और फसलों से जितना गहरा नाता है, उतना ही बीजेपी से भी जुड़ा है। ये हैं बांकुड़ा के गंगा के डूब वाले इलाके के आलोक कुमार सिंह। हल उनका हमेशा का साथी है। वे उसी हल पर दो सौ किलोमीटर का सफर तय करके कोलकाता आए। हल पर पोस्टर लगा था। उसे लेकर वे साल्टलेक में बीजेपी ऑफिस पहुंचे और और मांग की-मुझे टिकट दो, मैं चुनाव जीता तो कृषि मंत्री बनूंगा। हालांकि, आलोक अभी तक बंगाल बीजेपी के किसी बड़े नेता तक अपनी यह इच्छा नहीं पहुंचा पाए हैं। वे सभी उम्मीदवारों के चयन के लिए एक ज़रूरी मीटिंग के लिए दिल्ली में हैं। नतीजतन, बांकुड़ा के किसान इंतज़ार करने को मजबूर हैं। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने प्रस्ताव जारी करके राज्य के लोगों की राय इकट्ठा की है। उनका कहना था-2026 में राज्य में बदलाव होगा। बीजेपी नहीं, बल्कि जनता की सरकार आ रही है। आलोक कुमार सिंह पूरी रात ट्रेन से हल लेकर सॉल्टलेक स्थित बीजेपी ऑफिस शमिक भट्टाचार्य से मिलने पहुंचे। सफेद और नीले रंग की चेक वाली शर्ट, पैरों में प्लास्टिक की चप्पल, कंधे पर हल, उस पर एक पोस्टर- 'मैं कृषि मंत्री बनना चाहता हूं'। इतना ही नहीं, वे हल में कई और पोस्टर भी लगाकर लाए थे। पोस्टरों में स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरें थीं, तो कुछ पर नारा था- 'जय जवान, जय किसान'। असल में, आलोक ने दो साल पहले भी इसी हल से खेती की थी। तो कृषि मंत्री बनने की मांग में यह हल उनका साथी है। दूर बांकुड़ा से आए आलोक कुमार सिंह फिलहाल सॉल्टलेक स्थित बीजेपी ऑफिस के परिसर में ही रुके हुए हैं। उन्होंने कहा कि वे 1998 से बीजेपी से जुड़े हैं। 2018 के पंचायत चुनाव में आलोक के भाई और भाई की पत्नी दोनों उम्मीदवार थे। चुनाव के बाद उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। वे मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य के संपर्क में हैं। वे अपनी मांगें रखने उनके पास आए थे। बांकुड़ा की मिट्टी के आदमी आलोक की मांग भी बहुत जायज थी। जो सीधे तौर पर खेती से अपना गुज़ारा करता है, उसे सबसे पहले एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का चार्ज मिलना चाहिए। इसीलिए वे बीजेपी के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं। वे जीतने के इनाम के तौर पर कृषि विभाग चाहते हैं।

5.23 लाख मतदाता पहली बार करेंगे मतदान

निज संवाददाता : मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने बताया कि पश्चिम बंगाल में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में राज्य के 6,000 से ज्यादा ऐसे वोटर हिस्सा लेंगे जिनकी उम्र 100 साल पार कर चुकी है। इसके साथ ही 18 से 19 साल के 5.23 लाख नए वोटर पहली बार अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। राज्य में 20 से 30 साल के बीच के लगभग 1.31 करोड़ युवा वोटर हैं। चुनाव आयोग ने इस बार युवाओं की भागीदारी पर खास जोर दिया है। हर विधानसभा क्षेत्र में विशेष पंजीकरण अधिकारी तैनात होंगे।

ये अधिकारी कॉलेजों में जाकर युवाओं को चुनाव से जोड़ने के लिए अभियान चलाएंगे। आयोग का मकसद एक शुद्ध वोटर लिस्ट तैयार करना है ताकि कोई भी योग्य वोटर छूट न जाए और किसी गलत व्यक्ति का नाम शामिल न हो। बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए भी बड़े इंतजाम किए गए हैं। 85 साल से ज्यादा उम्र के लगभग 3.78 लाख वोटरों को घर से वोट डालने की सुविधा मिलेगी। सभी पोलिंग स्टेशन ग्राउंड फ्लोर पर बनाए जाएंगे ताकि किसी को परेशानी न हो। वहां रैंप और व्हीलचेयर का इंतजाम रहेगा और दिव्यांगों को वोट डालने में प्राथमिकता दी जाएगी। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 210 सामान्य हैं, जबकि 68 अनुसूचित जाति और 16 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। राज्य में कुल 80,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन होंगे, जिनमें से 61,000 ग्रामीण इलाकों में हैं। चुनाव में पूरी पारदर्शिता रखने के लिए सभी बूथों पर 100 प्रतिशत वेबकास्टिंग होगी। चुनाव आयोग के अधिकारी इसकी कड़ी निगरानी करेंगे। महिलाओं की सुविधा के लिए 8,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन पूरी तरह महिला स्टाफ मैनेज करेगा। इनमें से 600 को मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाया जाएगा। इस बार ईवीएम पर उम्मीदवारों की रंगीन फोटो होगी ताकि वोटर आसानी से अपने पसंदीदा उम्मीदवार को चुन सकें। भीड़ से बचने के लिए एक बूथ पर 1,200 से ज्यादा वोटर नहीं होंगे। पोलिंग स्टेशन के बाहर मोबाइल फोन जमा करने की सुविधा भी मिलेगी। चुनाव आयोग ने ईसीआईएनईटी (एसेनेट) नाम का एक नया एप भी पेश किया है। पहले के अलग-अलग ऐप्स की जगह अब सारी जानकारी इसी एक ऐप पर मिलेगी। बीएलओ घर-घर जाकर वोटर स्लिप देंगे, जिसमें बूथ की पूरी जानकारी होगी। राज्य में विधानसभा चुनाव अप्रैल में होने की संभावना है।

मनोरंजन

रिलीज से पहले ही 'धुरंधर 2' ने विदेश में मचाया धमाल

ग्लोबल बॉक्स ऑफिस प्री-सेल्स में कमाए 50 करोड़

निज संवाददाता : बॉलीवुड सुपरस्टार रणवीर सिंह एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर आग लगाने के लिए तैयार हैं। उनकी बहुप्रतीक्षित स्पाई एक्शन थ्रिलर धुरंधर: द रिवेंज (धुरंधर 2) ने अपनी रिलीज से एक हफ्ते पहले ही एडवांस बुकिंग के मामले में बड़े-बड़े रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। फिल्म ने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस प्री-सेल्स में ₹50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। विदेशों में, खासकर उत्तरी अमेरिकी बाजार (यूएसए और कनाडा) में फिल्म को लेकर जबरदस्त दीवानगी देखी जा रही है। ओपनिंग वीकेंड के लिए विदेशी बाजारों से अब तक लगभग ₹35 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। इसमें से अकेले ₹27 करोड़ केवल नॉर्थ अमेरिका से आए हैं। फिल्म की प्री-सेल्स ने धुरंधर के पहले पार्ट के ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन को अभी से पीछे छोड़ दिया है। आदित्य धर द्वारा निर्देशित इस सीक्वल ने 19 मार्च को फ़िल्म की रिलीज़ को लेकर ज़बरदस्त चर्चा पैदा कर दी है। फ़िल्म के प्रीव्यू शो 18 मार्च को आयोजित किए जाएंगे। फ़िल्म ने भारत में प्रीमियर शो के लिए चार लाख से ज़्यादा टिकट बेचे हैं। अभी तक, धुरंधर 2 ने भारत में 18 मार्च के प्रीमियर शो से लगभग 21.50 करोड़ रुपये की कमाई की है। विदेशी बाज़ारों, विशेष रूप से उत्तरी अमेरिका ने, एडवांस सेल्स में बहुत बड़ा योगदान दिया है। पूरे ओपनिंग वीकेंड के लिए विदेशी प्री-सेल्स लगभग 35 करोड़ रुपये है, जिसमें से 27 करोड़ रुपये उत्तरी अमेरिका से आए हैं। बताया जाता है कि फ़िल्म की दुनिया भर की प्री-सेल्स पहले ही 56+ करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है। अन्य देशों में फ़िल्म की प्री-सेल्स ने पहली धुरंधर फ़िल्म के ओपनिंग वीकेंड की कमाई को पहले ही पीछे छोड़ दिया है। फ़िल्म प्री-सेल्स में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने की स्थिति में तो नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि धुरंधर 2 का कुल आंकड़ा 150 करोड़ रुपये से ज़्यादा होगा, क्योंकि भारत में फ़िल्म की बुकिंग अभी शुरू होनी बाकी है। जिन लोगों को नहीं पता, उनके लिए बता दें कि धुरंधर 2, जिसका टाइटल धुरंधर: द रिवेंज है, 19 मार्च 2026 को हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज़ होगी। इस सीक्वल में रणवीर सिंह के साथ सारा अर्जुन, अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी, आर. माधवन और दानिश पंडोर नज़र आएंगे। फिल्म में अक्षय खन्ना भी कैमियो करेंगे।

'कबीर बेदी ने सैंडोकन' के 50 साल पूरे होने का जश्न मनाया

निज संवाददाता : मशहूर अभिनेता कबीर बेदी की अंतरराष्ट्रीय टीवी सीरीज 'सैंडोकन' के 50 वर्ष पूरे हो गए है। इस अवसर पर कबीर बेदी ने जमकर जश्न मनाया। यह जश्न इटली के प्रतिष्ठित सैनरेमो म्यूजिक फेस्टिवल में मनाया गया, जहां कबीर बेदी ने इस यादगार पल को बेहद भावुक और गौरवपूर्ण बताया। इस समारोह में उनके साथ तुर्की अभिनेता केन यामन भी मौजूद थे, जो सैंडोकन के नए संस्करण में इस प्रतिष्ठित किरदार को निभाते नजर आएंगे। दरअसल, साल 1976 में प्रसारित हुई 'सैंडोकन' इटालियन टेलीविजन की सबसे लोकप्रिय और सफल सीरीज में गिनी जाती है।इस शो का निर्देशन प्रसिद्ध फिल्मकार सेरजियो सोलिमा ने किया था। सीरीज में कबीर बेदी ने 'सैंडोकन' नाम के एक साहसी और करिश्माई समुद्री डाकू का किरदार निभाया था। यह भूमिका इतनी लोकप्रिय हुई कि कबीर बेदी यूरोप सहित दुनिया के कई देशों में सुपरस्टार बन गए। खास बात यह भी रही कि वह उन शुरुआती भारतीय अभिनेताओं में शामिल थे, जिन्होंने किसी बड़े अंतरराष्ट्रीय टीवी शो को लीड किया और वैश्विक स्तर पर पहचान बनाई। इटली में आयोजित इस समारोह की तस्वीरें कबीर बेदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी साझा कीं। उन्होंने बताया कि 24 फरवरी को हुए इस विशेष कार्यक्रम में नए 'सैंडोकन' कैन यमन से मिलना उनके लिए बेहद खास अनुभव रहा। अभिनेता ने लिखा कि यह पल उनके लिए भावुक कर देने वाला था, क्योंकि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि 50 साल बाद वह फिर से सैनरेमो में इस सीरीज के जश्न का हिस्सा बनेंगे।

महाकुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा ने रचाई शादी

मुस्लिम बॉयफ्रेंड ने मांग में भरा सिंदूर

निज संवाददाता : साल 2025 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेले के दौरान माला बेचने वाली मोनालिसा अपनी गहरी नीली और बड़ी-बड़ी आंखों की वजह से खूब सुर्खियों में रहीं और देखते ही देखते वे महाकुंभ वायरल गर्ल बन गईं। वहीं महाकुंभ वायरल सेंसेशन मोनालिसा ने बीते दिन अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड फरमान खान से शादी कर हर किसी को चौंका दिया। मोनालिसा ने ये शादी केरल में तिरुवनंतपुरम के पास पूवर में अरुमानूर श्री नैनार देवा मंदिर में की। उनकी शादी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वायरल हो रही वीडियो में देखा जा सकता है कि मोनालिसा लाल साड़ी पहने हुए नजर आ रही हैं। तिरुवनंतपुरम के अरुमनूर नैनार मंदिर में उनके बॉयफ्रेंड फरमान कई लोगों की मौजूदगी में उनकी मांग में सिंदूर भरते हुए और उन्हें मंगलसूत्र जैसा धागा पहनाते हुए दिख रहे हैं। इस दौरान दोनों काफी खुश नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, मोनालिसा मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली हैं, और उनके पति फरमान महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। दोनों डेढ साल से रिलेशनशिप में थे। हालांकि, इस कपल को मोनालिसा के पिता, जय सिंह भोसले से काफी विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि वे अलग-अलग धर्मों के हैं। यह भी आरोप है कि उन्होंने मोनालिसा पर एक दूर के रिश्तेदार से ज़बरदस्ती शादी करने का दबाव डाला था। मुस्लिम बॉयफ्रेंड संग शादी करने के बाद मोनालिसा ने मीडिया से बात करते हुए कहा-मेरा परिवार मेरी शादी कहीं दूर करना चाहता था, लेकिन मुझे यह पसंद नहीं आया... लेकिन अब मैं खुश हूं...

मोनालिसा हाल ही में पूवर में अपनी पहली मलयालम फ़िल्म नागम्मा की शूटिंग कर रही थीं। खबर है कि उनके पिता ने उन्हें ढूंढ लिया और ज़बरदस्ती अपने होमटाउन वापस ले जाने की कोशिश की। इस घटना के बाद, मोनालिसा और फरमान केरल की राजधानी के थम्पनूर पुलिस स्टेशन गए और सुरक्षा मांगी। शिकायत दर्ज कराने के बाद, उनके पिता को पुलिस स्टेशन बुलाया गया। पुलिस ने परिवार से कहा कि चूंकि मोनालिसा 18 साल की हैं, इसलिए उन्हें यह तय करने का कानूनी अधिकार है कि वह किसके साथ रहना चाहती हैं।

बाद में मोनालिसा अपने बॉयफ्रेंड के साथ स्टेशन से चली गईं, और कपल ने एक मंदिर में शादी कर ली। केरल के कई बड़े नेता कपल को सपोर्ट करने के लिए आए, जिसमें केरल के शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी भी शामिल थे, जिन्होंने इस इवेंट को ''असली केरल की कहानी'' बताया। एमनी गोविंदन (माकपा राज्य सचिव) और एए रहीम (सांसद) भी मौजूद थे।

कलम के जरिए व्यवस्था के खिलाफ आग उगलने वाले बॉलीवुड के बागी शायर

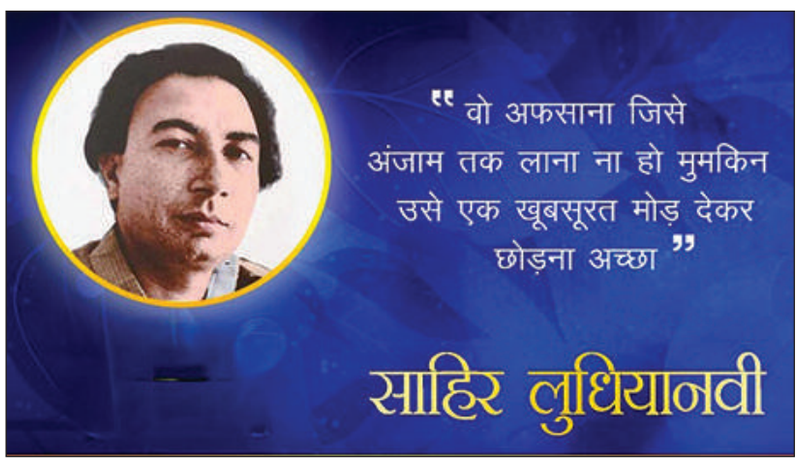

निज संवाददाता : 20वीं सदी के सबसे बेहतरीन गीतकार और कवि में से एक रहे साहिर लुधियानवी का 8 मार्च को जन्म हुआ था। साहिर के गीतों और शायरी को आज भी लोग खूब पसंद करते हैं। उन्होंने अपने गीतों और शायरियों के जरिए जुल्मों और गैर-बराबरी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की थी। साहिर लुधियानवी शब्दों के सच्चे जादूगर थे। पंजाब के लुधियाना के करीमपुरा में 8 मार्च 1921 को साहिर लुधियानवी का जन्म हुआ था। वह एक पंजाबी मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखते थे। साहिर का असली नाम अब्दुल हई है। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा लुधियाना से पूरी की। कॉलेज टाइम से ही वह अपने शेर और शायरी के लिए फेमस हो गए थे। साहिर एक भारतीय कवि और संगीतकार थे। उन्होंने हिंदी फिल्मों के लिए तमाम गाने भी लिखे। साहिर लुधियानवी ने अपने काम से फिल्म जगह में अच्छी जगह बनाई थी। साल 1949 में आई फिल्म आजादी की राह से उन्होंने अपने करियर की शुरूआत की थी। इस फिल्म के लिए उन्होंने 4 गाने लिखे थे। फिर साल 1951 में आई फिल्म नौजवान के लिए साहिर ने गाने लिखे। उनको सबसे अधिक सफलता साल 1951 में आई फिल्म बाजी से मिली थी। इन गानों के संगीतकार एस डी बर्मन थे। उस दौरान साहिर को गुरुदत्त की टीम का हिस्सा माना जाता है। बर्मन के साथ साहिर की आखिरी फिल्म प्यासा थी। इसके बाद दोनों के बीच कुछ मतभेद हो गए। जिसका कारण बर्मन और साहिर की राहें अलग हो गईं। साहिर लुधियानवी की कविताएं और शायरी दत्ता नायक को काफी ज्यादा पसंद थीं। जिस कारण साहिर ने दत्ता नायक के साथ तमाम फिल्मों के लिए गाने लिखे थे। साहिर लुधियानवी ने फिल्म चंद्रकांता, दास्तान, मिलाप, इज्जत और दाग के लिए भी गाने लिखे थे।

बताया जाता है कि साहिर लुधियानवी ने लता मंगेशकर से ज्यादा फीस की डिमांड की थी। साहिर का कहना था कि भले ही उनको लता से एक रुपए ही ज्यादा दिया जाए, लेकिन उनको लता से ज्यादा फीस दी जाए। जिसके कारण साहिर और लता के बीच मतभेद हो गए थे। 25 अक्तूबर 1980 को 59 साल की उम्र में साहिर लुधियानवी ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था। जिसके बाद उनको मुस्लिम रीति-रिवाज के साथ जुहू में दफनाया गया था।

स्वामी मोहता पब्लिशिंग हाउस के लिए, प्रकाशक, मुद्रक : अजय कुमार मोहता द्वारा अरिहंत मुद्रा, 61, सूर्यसेन स्ट्रीट, कोलकाता-700009 से मुद्रित एवं प्रकाशित। **संपादकीय कार्यालय :** 10, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद सरणी, (क्लाइव रो), 5बी मंजिल, रूम नं. 9, कोलकाता-700001, **स्थानीय कार्यालय :** 28-5 कन्वेंट रोड, मौलाली, कोलकाता-700014। **संपादक : अजय कुमार मोहता,** मो. 9830045693, E-mail-gambheersamachar@gmail.com. Website. www.gambheersamachar.in (प्रकाशित रचनाओं के चयन, संपादन हेतु पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी, सभी कानूनी विवाद के लिए कोलकाता न्याय क्षेत्र)